राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 13 अगस्त 2025 वर्ष-8,अंक-175 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पवित्रता का हवाला देकर प्रस्ताव खारिज: ऑनलाइन नहीं बिकेगा पुरी जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद

पुरी (एजेंसी)। ओडिशा सरकार ने साफ कर दिया कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ऑनलाइन बेचने की अनुमति नहीं दे सकती। इस आशय का प्रस्ताव खारित करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि ये महाप्रसाद की पवित्रता का सवाल है इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, महाप्रसाद का गहरा धार्मिक महत्व है और इसे सर्वोच्च सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए। यह पारंपरिक रूप से केवल मंदिर परिसर में ही बेचा जाता है, और अगर इसे ऑनलाइन बेचा गया तो इसकी पवित्रता से समझौता हो सकता है। उनका यह बयान एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा महाप्रसाद बेचने के प्रयास के बाद सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं के जवाब में आया है। उन्होंने कहा, 'हमें डर है कि अगर 'महाप्रसाद' को इस तरीके से श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गया तो इसकी शुद्धता कायम रह पाएगी या नहीं।' हरिचंदन ने कहा कि सरकार ऐसी किसी भी पहल का समर्थन या प्रचार नहीं करती है। उन्होंने कहा, 'न तो हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव है और न ही हम किसी को 'महाप्रसाद' को ऑनलाइन बेचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।' कानून मंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे 'महाप्रसाद' ग्रहण करने के लिए पुरी जगन्नाथ मंदिर आएं। उन्होंने कहा कि 'महाप्रसाद' के लिए संशोधित दर जल्द लागू की जाएगी। मंत्री का यह बयान मीडिया की उन खबरों के बाद आया है जिनमें भगवान जगन्नाथ के 'महाप्रसाद' की बिना अनुमति ऑनलाइन बिक्री का आरोप लगाया गया है। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के 'महाप्रसाद' की ऑनलाइन बिक्री के कुछ संगठनों के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। हरिचंदन ने यहां सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि कुछ संगठनों ने हाल में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) से पुरी मंदिर के 'महाप्रसाद' और 'सूखा प्रसाद' को ऑनलाइन मंचों के माध्यम से श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, 'दुनियाभर के श्रद्धालुओं को प्रसाद उपलब्ध कराना एक अच्छा विचार था, लेकिन सरकार और एसजेटीए ने प्रसाद की शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।'

श्रीनगर में अलगाववादी यासीन के घर समेत 8 जगह पर छापे

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर की स्टेट इंवेस्टीगेशन एजेंसी की मंगलवार को श्रीनगर के 8 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मामला अप्रैल 1990 में घाटी में आतंकवाद के चरम के दौरान कश्मीरी पंडित महिला सरला भट के अपहरण-हत्या से जुड़ा है। जिन जगहों पर एसआईए की रेड जारी है, उनमें जेके लिब्रेशन फ्रंट के पूर्व चीफ यासीन मलिक का मैसूमा स्थित घर भी शामिल है। यहां डिप्टी सीएम आबिद हुसैन, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट और दूसरे पुलिसकर्मी जांच के लिए पहुंचे हैं। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन का बेटा गुलाम कादिर मलिक भी तिहाड़ में ही बंद है। अधिकारियों ने बताया- ये छापे संख्या 56/1990, धारा 302, 120 , 3/27 आर्म्स एक्ट और 3/2 टाडा के तहत दर्ज किए गए थे।

इजराइल ने 60 हजार लोगों को मारा, सरकार है खामोश

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को गाजा में हुई हत्याओं की कड़ी निंदा की और इजराइल पर 'नरसंहार' करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने गाजा में 60 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा पर चुप है, जबकि इजराइल नागरिकों पर तबाही बरपा रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने प्रियंका गांधी के सवालों के जवाब में कहा कि यह गलत बयान है। वहां आम लोगों के मौत की वजह हमास है। वायनाड सांसद प्रियंका ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि गाजा में सैकड़ों लोगों की मौत भूख से हुई है और लाखों लोग भुखमरी के खतरे में हैं। उन्होंने गाजा में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की टारगेट किलिंग को 'जघन्य अपराध' बताया। एक अन्य पोस्ट में प्रियंका ने लिखा कि चुप्पी के जरिए ऐसे अपराधों को बढ़ावा देना भी अपराध है। उन्होंने भारत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि वह तब भी चुप है जब इजराइल लोगों पर कहर बरपा रहा है।

फतेहपुर मकबरा और मंदिर बवाल पर जमकर हंगामा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन फतेहपुर में मकबरे-मंदिर विवाद की घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने इस मुद्दे को उठाते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि फतेहपुर में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती है कि यूपी में शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षिय राजनीति इनकी चल सके। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सपा नेता व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बताया कि एक पार्टी के नेता ने एलान किया कि ये मकबरा हिंदुओ का है, हम इस पर कब्जा करेंगे। बड़ी संख्या में लोगों को लेकर वहां पहुंच गए थे। पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की थी।

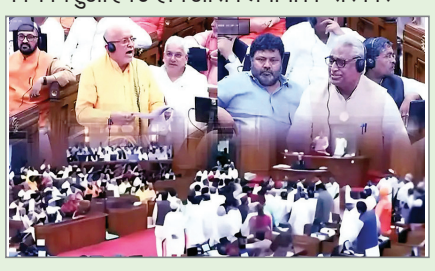

देश में आय आधारित हो आरक्षण व्यवस्था!

● पीआईएल पर सुनवाई को तैयार एससी, छिड़ सकती है नई बहस

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने पर अपनी सहमति दे दी है, जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अधिक न्यायसंगत व्यवस्था के लिए नीतियां बनाने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद की जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है और 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मसले पर सुनवाई करने के लिए सहमति देने के बाद देश में आरक्षण पर नई बहस छिड़ सकती है। पीठ ने भी याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह भारी विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस जनहित याचिका के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता संदीप सिंह के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 को मजबूत करेगा और मौजूदा आरक्षण सीमा में बिना किसी छेड़छाड़ के समान अवसर सुनिश्चित करेगा। याचिका में कहा गया है कि दशकों से आरक्षण के बावजूद, आर्थिक रूप से सबसे वंचित लोग अकसर पीछे छूट जाते हैं और आरक्षित श्रेणियों के अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले लोग इसका लाभ उठाते हैं लेकिन आय के आधार पर प्राथमिकता देने से यह सुनिश्चित होगा कि मदद वहीं से शुरू हो जहां आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। जनहित याचिका में कहा गया है,इन समुदायों के भीतर असमानता उजागर करना चाहते हैं।

कैबिनेट मीटिंग में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

सरकार 4,594 करोड़ रुपए निवेश करेगी लखनऊ में मेट्रो के अगले फेज को मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 18,541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और आज 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे घरेलू चिप उत्पादन, पैकेजिंग और एडवांस्ड मटेरियल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दो हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.165 किलोमीटर लंबाई वाली लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज-1बी को मंजूरी दी है। इसके तहत 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और जिसके लिए 5,801 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। लखनऊ में मेट्रो की बहुत जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत स्वच्छ विकास और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध है।

बिहार में बाढ़ का कहर, 17 लाख लोग प्रभावित, उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा रोकी

--मध्यप्रदेश-यूपी समेत 16 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली(एजेंसी)। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 17 लाख से ज्यादा की आबादी इससे प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में भागलपुर है, यहां की 75 पंचायतों के 4.16 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। लखनऊ में तेज बारिश हुई, जिससे विधानसभा परिसर में पानी भर गया। सीएम आवास के पास सड़क पर 2 फीट तक पानी भर गया।

उत्तराखंड के देहरादून में भी तेज बारिश हुई। यहां का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पानी के तेज बहाव में कई गायें बहती नजर आईं। मंगलवार को जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं, मालदेवता क्षेत्र में नदी ने आसपास बने मकानों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में 12 से 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी वजह से केदारनाथ धाम यात्रा 3 दिन के लिए रोक दी गई है।

मंगलवार सुबह से ही दिल्ली में तेज बारिश हो रही है जिससे कई जगहों पर पानी भर गया है। मौसम खराब होने के कारण 300 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ीं।

मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तराखंड, असम समेत 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, हिमाचल-बिहार समेत तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट और मध्यप्रदेश-यूपी समेत 16 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं बिहार में सामान्य से कम बारिश होने के बावजूद बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई है। छपरा, खगड़िया, बेगूसराय और पटना के दियारा इलाकों समेत कुछ जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया है। बाढ़ पीड़ित या तो घर की छतों पर शरण लिए हुए हैं या फिर सड़क पर आ चुके हैं। पटना में सड़क पर तंबू टेंट लगा कर मवेशियों के रहने और चारे की व्यवस्था की गई है। ये सभी मवेशी और पशुपालक दियारा इलाकों के हैं जो गंगा के रौद्र रूप के चलते मरीन ड्राइव के पास आ गए हैं। खगड़िया में एक ओर जहां गंगा नदी खतरे के निशान से 1.68 मीटर ऊपर बह रही है, वहीं बूढी गंडक नदी भी 1.15 मीटर खतरे के निशान से उपर है, जिसके कारण कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। खगड़िया के 4 प्रखंडों की 17 पंचायतें बाढ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा परेशानी परबत्ता और सदर प्रखंड में है। दुर्गापुर प्रखंड के दुर्गापुर गांव में 200 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पूरा गांव बाढ़ के पानी से घिरा है। कई लोग तो छतों पर शरण लिए हुए हैं। छतों पर ही चूल्हा जला कर खाना बनाया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि पहले से ही बाढ़ के पानी से परेशान हैं, ऊपर से बारिश के कारण छत पर भी रहना मुश्किल है। जो भी सूखी लकड़ियां हैं, वह गीली हो गई हैं। ऐसे में खाना बनाने में भी दिक्कत हो रही है। खगड़िया के डीएम ने बताया कि प्रभावित इलाकों में सौ से ज्यादा नाव चलाई गई हैं। जरुरत के मुताबिक कम्युनिटी किचन भी शुरू किया गया है। बेगूसराय में गंगा में आई बाढ़ से आठ प्रखंड में ढाई लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा परेशानी भोजन की। भोजन की परेशानी को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। प्रशासन की ओर 83 जगह पर सामुदायिक किचन के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा-कोई ऐसे नहीं बन जाता भारत का नागरिक

सिर्फ आधार, पैन या वोटर आईडी कार्ड नहीं है नागरिकता का प्रमाण

मुंबई (एजेंसी)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज रखने से कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता। कोर्ट ने यह टिप्पणी कथित तौर पर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए की। जमानत अर्जी दाखिल करने वाले उक्त व्यक्ति पर जाली और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में एक दशक से भी अधिक समय तक रहने का आरोप है। जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है और नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज केवल पहचान या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हैं। कोर्ट ने कथित बांग्लादेशी नागरिक बाबू अब्दुल रऊफ सरदार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया हो गई शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। स्पीकर ने कहा, मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के 1-1 जज और 1 कानूनविद शामिल हैं। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक यह महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के घोषित कानूनों के साथ-साथ कई अन्य फैसलों की जानकारी भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया है। इनहाउस प्रक्रिया का पालन किया।

बिहार वोटर वेरिफिकेशन **सुप्रीम कोर्ट ने कहा-तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, सवाल तो उठेंगे**

सिब्बल-12 जिंदा लोग मृत बताए, ईसी-कुछ गलतियां स्वाभाविक

पटना (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर (सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन) पर सुनवाई हुई। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा- बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा- इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थीं। यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया, यह सही किया जा सकता है, क्योंकि यह एक मसौदा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों वालों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में सुनवाई हो रही है। इससे पहले 29 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटे हैं, तो हम हस्तक्षेप करेंगे। एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं, कुछ मर गए हैं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था-अगर खामी मिली तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। साथ ही चुनाव आयोग से पूछा था कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा था,राशन कार्ड पर विचार नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़े पैमाने पर बना है, फर्जी होने की संभावना अधिक है। एससी ने कहा था-अगर बात फर्जीवाड़े की है तो धरती पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसकी नकल नहीं हो सके।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आओ नारी शक्ति को भारत की सफ़लता की गाथा बनाएं

साथियों बात अगर हम माननीय पीएम नीति आयोग में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीयों व विशेषज्ञों से बातचीत की करें तो उन्होंने भी,नारी शक्ति को भारत के विकास के प्रमुख इंजन के रूप में चिन्हित किया और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को और सक्षम बनाने के साथ-साथ उसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखने का आग्रह किया, उन्होंने आज नीति आयोग में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की।विचार-विमर्श वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और दृढ़ता विषय पर आधारित था। अपनी टिप्पणी में कहा कि, जहां जोखिम थे, वहीं उभरता हुआ वैश्विक वातावरण डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर प्रदान करता है।

(लेखक- किशन सनमुखदास भावनानी)

वैश्विक स्तरपर भारतीय नारी की गाथा बहुत ही सम्मानजनक रूप से गाई जाती है, क्योंकि आदि अनादि काल से ही भारतीय नारी शक्ति की अनेक मान्यता प्राप्त कहानियों कथाओं से भी हमें पता चलता है कि नारी शक्ति की शक्ति तो देवी-देवताओं को भी करनी पड़ी थी, हम तो इस कलयुग में इंसान मात्र हैं। इसलिए हमें चाहिए कि नारी शक्ति का सम्मान कर उनको कार्यबल प्रदान करें जिसको भारत के विकास में प्रमुख इंजन के रूप में चिन्हित कर एक फ़रवरी 2026 को आने वाले बज़ट में ऐसी योजनाओं स्कीमों को लाया जाना चाहिए ताकि नारी शक्ति को कार्य बल में उचित भागीदारी मिले और भारत के तेज़ी से विकसित हो रहे पथ को अधिक तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। साथियों बात अगर हम नारी शक्ति को कार्यबल के रूप में चिन्हित करने की करें तो, हमने कई क्षेत्रों में देखे हैं कि नारी कार्यबल अपेक्षाकृत रूप से अधिक सशक्त व प्रभावी रिजल्ट देता है। हम अगर नर नारी के कार्यबल की गुणवत्ता का विश्लेषण करें तो, मेरा मानना है कि नारी बल गुणवत्ता में अधिक कुशल दिखेगा। जिसका मैंने खुद ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सत्यता परखी है। मैंने अनेक शोरूम ऑफिसेस दवाखाना वकील सीए अनेक प्रोफेशनल जगह कंपनियों में वहां के प्रमुख संचालकों, मैनेजरों अधिकृत व्यवस्थापकों से बात की तो उन्होंने भी नारी कार्यबल को अपेक्षाकृत अधिक सशक्त इमानदार रेगुलर जिम्मेदार ज़वाबदेही में अवल बताया और नारी कार्यबल को प्राथमिकता देने की बात स्वीकार की, क्योंकि नकारात्मक आदतें नारी कार्यबल में नहीं देखने को मिलती जितनी नर कार्यबल में देखने को मिलती है। उसी तरह नेतृत्व शक्ति में भी नारी कार्यबल अधिक उच्च गुणवत्ता में अग्रणी ही है इसका उदाहरण हमें वैश्विक स्तरपर मूल भारतीय महिलाओं कल्पना चावला कमला हैरिस सहित अनेकों का नाम लिया जा सकता है।

साथियों बात अगर हम 1 फ़रवरी 2026 को आने वाले बजट में नारी शक्ति कार्यबल के एंगल से देखें तो आज इसकी कार्य शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक बजट एलोकेशन की आवश्यकता है। कुछ ऐसी योजनाएं, इंसेंटिव, छूट दी जानी चाहिए ताकि नारी कार्यबल को प्राथमिकता दिए जाने पर प्रोत्साहन मिले। वैसे भी हम अभी अनेकों निजी कंपनियों में देखते हैं कि वहां नारी कार्यबल को प्राथमिकता दी जाती है जो वर्तमान समय की जरूरत भी है अब वक्त आ गया है कि नारी शक्ति के कार्य बल को बढ़ाने आरक्षण का बंधन भी तोड़ने की ज़रूरत है और उच्च कौशल्या के आधार पर नारी कार्यबल की सेवा राजनीतिक, औद्योगिक शैक्षणिक सहित हर क्षेत्र में ली जानी चाहिए। भारतीय कौशल नारी सबपर भारी की थींम को आगे बढ़ाया जाए

साथियों बात अगर हम माननीय पीएम नीति आयोग में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीयों व विशेषज्ञों से बातचीत की करें तो उन्होंने भी,नारी शक्ति को भारत के विकास के प्रमुख इंजन के रूप में चिन्हित किया और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को और सक्षम बनाने के साथ-साथ उसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखने का आग्रह किया, उन्होंने आज नीति आयोग में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की।विचार-विमर्श वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और दृढ़ता विषय पर आधारित था। अपनी टिप्पणी में कहा कि, जहां जोखिम थे, वहीं उभरता हुआ वैश्विक वातावरण डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर प्रदान करता है। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल का लाभ उठाने और लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। उन्होंने भारत डिजिटल की सफलता की गाथा और देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाने, और समावेशी विकास और इसके दृढ़ संकल्प की क्षमता की सराहना की। बैठक में प्रतिभागियों ने उन तरीकों पर व्यावहारिक उपायों की पेशकश की, जिनसे भारत अपने विकास की गति को विवेकपूर्ण ढंग से बनाए रख सकता है। कृषि से लेकर विनिर्माण तक विविध विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ विचार और सुझाव साझा किए गए। यह स्वीकार करते हुए कि अंतर्निहित वैश्विक प्रतिकूलताएं जारी रहने की संभावना है,

भारत की दृढ़ता को और मजबूत करने के लिए रणनीतिक सिफारिशें भी साझा की गईं। इस बात पर सहमति कायम हुई कि अपने लचीलेपन के कारण, भारत अशांत वैश्विक मंच पर एक उज्ज्वल स्थान बनाकर उभरा है। यह सुझाव दिया गया था कि सभी क्षेत्रों में समग्र विकास के माध्यम से इस नींव पर नए सिरे से विकास पर जोर देने की आवश्यकता होगी। हर नारी अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर पाये , अपने अरमानो को पंख लगाने का जज्बा रखे और उन्हें पूरा करने का होंसला रखे । किसी से कोई खैरात नहीं, कोई पक्षपात नहीं , अपने बलबूते पर मंज़िल हांसिल करने माद्दा रखे। साथियों बात अगर हम बड़ी संख्या में अभी भी महिलाओं की वर्तमान स्थिति की करें तो, वर्तमान युग में महिलाओं को मात्र भोग विलास की वस्तु बना कर रख दिया गया है। जिसका मूल काम घर में रहकर चूल्हा चौका करना तथा परिवार की देखभाल करना रह गया है। आज के समय जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का कुछ ऐसा वर्ग भी है जिन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इस कुप्रथा को दूर करने के लिए हर किसी को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलकर स्त्रियों को साथ नहीं लेंगे तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास मुमकिन नहीं हो पाएगा।भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि उसके विकास में पुरुष तथा स्त्रियों का समान प्रयास हुआ करता था। लेकिन जैसे-जैसे स्त्रियों के विकास का अनुपात कम होता गया वैसे वैसे भारत का गौरव भी धूमिल पड़ता गया।भारतीय महिलाओं का इतिहास में योगदान अप्रतिम रहा है। सिर्फ स्वाधीनता संग्राम के समय को देखा जाए तो भारतीय महिलाओं का योगदान अगणनीय ही प्राप्त होगा। स्वाधीनता संग्राम के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई, विजयालक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरु, सुचेता कृपलानी, मणीबेन पटेल अमृत कौर जैसी स्त्रियों ने आगे आकर अपना अप्रतिम योगदान दिया।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारतीय कौशल नारी सबपर भारी। आओ नारीशक्ति को भारत की सफ़लता की गाथा बताएं। नारी शक्ति को भारत के विकास के प्रमुख इंजन के रूप में चिन्हित करने की योजनाएं बनाना ज़रूरी। बजट 2026 में नारी शक्ति को चिन्हित कर कार्यबल में भागीदारी की योजना स्कीम लाना समय की मांग है।

(-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र)

संपादकीय

मुनाफे की चिकित्सा- शिक्षा

हाल के वर्षों में शिक्षा और चिकित्सा का जिस तेजी से बाजारीकरण हुआ है, उसने आम आदमी को बदहाली के कगार पर पहुंचाया है। महंगी शिक्षा ने जहां अभिभावकों का बजट हिला दिया है, वहीं चिकित्सा के नाम पर मुनाफाखोरी ने लाखों परिवारों को गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। इस मर्ज की रग पर हाथ रखते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दी गई चेतावनी सत्ताधीशों की आंख खोलने वाली है। इंदौर में एक किफायती कैंसर देखभाल केंद्र का उद्घाटन करते हुए भागवत ने चेताया कि भारत में स्वास्थ्य-शिक्षा को सामाजिक दायित्व मानने की परंपरा रही है। दुर्भाग्य से आज स्कूल-कॉलेज और अस्पताल लाभ संचालित उपक्रमों में तब्दील हो गए हैं। मुनाफाखोरी की अंतहीन लिप्सा ने कथित गुणवत्ता वाले स्कूलों व अस्पतालों को आम आदमी की पहुंच से दूर किया है। उन्होंने कॉर्पोरेट शैली के कथित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के जुमले के बजाय लोककल्याण के धार्मिक सिद्धांतों के अनुसरण की अपील की। निस्संदेह,यह चिंता हमारे समय की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती है। आज आम भारतीय परिवारों पर स्वास्थ्य सेवाओं का भारी वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। विडंबना यह है कि इस खर्च का छोटा हिस्सा ही सरकारी खजाने से वहन किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य खर्च का महज 17 फीसदी है। वहीं करीब 82 फीसदी स्वास्थ्य खर्च लोगों को मुश्किल हालात में वहन करना पड़ता है। इन स्थितियों के चलते अस्पताल में भर्ती होने के बाद कई परिवार जीवन भर के लिये कर्ज में डूब जाते हैं। तो कई परिवार हमेशा के लिये गरीबी की दलदल में धंस जाते हैं। आज देश की बड़ी आबादी गैर संक्रामक रोगों, मसलन हृदय रोग,मधुमेह व उच्च रक्तचाप आदि से जूझ रही है। इनकी जांच, चिकित्सकीय परामर्श और उपचार के लिये मरीजों को एक बड़ी रकम चुकाने को मजबूर होना पड़ता है। जो कि बीमा योजनाओं के द्वारा बमुश्किल ही पूरी की जाती है। कमोबेश, शिक्षा की भी यही स्थिति है। सरस्वती के मंदिर आज व्यापार के केंद्र बन गये हैं। अभिभावकों को उल्टे उस्तरे से मूंडने के लिये नये-नये तौर-तरीके निकाले जा रहे हैं। ट्यूशन फीस ही नहीं, एडमिशन फीस, बिल्डिंग फीस, ट्रांसपोर्ट जैसे तमाम मदों के नाम पर अभिभावकों का दोहन किया जाता है। इतना ही नहीं किताबें व ड्रेस तक शिक्षण संस्थानों की हिस्सेदारी वाली दुकानों से खरीदने को बाध्य किया जाता है। यहां तक कि आम शहरों में, माता-पिता प्रति बच्चे पर सालाना साठ हजार से भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। कुछ अभिभावक तो अपनी आय का लगभग आधा हिस्सा ट्यूशन और शिक्षा से जुड़े मदों पर खर्च कर रहे हैं। पिछले दिनों तब जनाक्रोश चरम पर नजर आया जब हैदराबाद के एक स्कूल में नर्सरी में दाखिले की सालाना फीस ढाई लाख रुपये बतायी गई। जिससे अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त हो गया। जिसके बाद महंगी होती शिक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई। निस्संदेह, बढ़ती फीस के ये आंकड़े शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण को भी रेखांकित करते हैं।

भाग्य अपना अपना है कोई झोपड़ी में खुश है तो महलों में भी रोता है

(लेखक- नरेंद्र भारती)

भाग्य अपना अपना है कोई झोपड़ी में खुश है तो महलों में भी रोता है .भाग्य किसी की बपोती नहीं होती कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है अच्छे कर्म करते रहिए .अपना अपना भाग्य होता है . कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा . कर्म प्रधान होता है इसलिए कर्म करते रहिए .भाग्य किसी क़ो भी मिट्टी में मिला सकता है . भाग्य एक पल में किसी क़ो कंगाल बना दे यह किसी क़ो पता नहीं होता . दो जून की रोटी क़ो तरसने वाले आज अपना समय भूल चुके हैं अच्छे कर्म करते रहिये जीवन स्वर्ग बन जायेगा ..आज कुछेक तथाकथित लोग तिगड़म करके ऐसे पदों पर विराजमान है जिसके वे काबिल नहीं है लेकिन सिफारिश के बलबूते स्थान हासिल करने वालों को एक दिन वक्त ज. र धूल चटाता है जब वह प्रतिभा के आगे नहीं टिकता एक कहावत की घर का जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध आज पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। मगर मानव को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मुसीबत में अपने ही काम आते है बाहर के तमाशा देखते हैं। आज अपनों को नीचे गिराया जाता है और बाहर के लोगों को उपर उठाया जाता है भेदभाव किया जाता है प्रतिभा को दबाया जाता है और चंद स्वार्थों के लिए बाहर के लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है ।आज कितने ही प्रतिभावान लोग है जिन्हे दरकिनार करके अयोग्य लोगों को मौका दिया जाता है।अनुभवहीन लोग आज इतने बड़े बन जाते है कि दूसरों को पाठ पढ़ाने लगते है कि कौन काम सही है और कौन गलत मगर सच्चाई सौ परदे फाड़ कर बाहर आती है तब ऐसे लोग खाक में मिल जाते है यह वक्त का कैसा तकाजा है कि आज सच्चे व इरादों के पक्के लोगों को मुख्यधारा से बाहर कियक्त एक ऐसा तराजू है जिसके एक पलड़े में जिन्दगी और दूसरे पलड़े में मौत होती है जीवन और मृत्यु में सिर्फ सांसों का फासला है।जब इन्सान जिन्दा होता है तो कोई उसका हाल तक नहीं पूछता लेकिन जब संसार से . खस्त हो जाता है तो हर आदमी मातम में शामिल होने में अपनी शान समझतें है। जिन्होने जब जिन्दा था तो बात तक नहीं की होंगी। जब जीता है तो एक जोड़ी कपड़ा तक नसीब नहीं होता मगर जब उसके किसी काम का नहीं होता उसके मृत शरीर पर सैंकड़ों चादरें डाली जाती है।जीते जी जिसे घी नहीं मिलता जलाती बार मुहं में शुद्ध देशी घी की आहुती दी जाती है जो व्यर्थ है।कहने का तात्पर्य यह है कि मानव की जीते जी सहायता कि जाए तो वही सच्ची मानवता कहलाएगी. आत्मकेन्द्रित लोग बहुत ही घातक होते हैं बस अपना काम हो जाए दुनिया भाड़ में जाए।समाज में ऐसे लोग किसी क़े नहीं होते है।आज भूखी जुएं अपनी औकात भूलकर ऐसे इतराती है कि जैसे खानदानी रईस हो पर वक्त के पास हर आदमी का लेखा-जोखा है कि कौन रईस था और कौन दाने-दाने को मोहताज था। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए हर आदमी से समानता का व्यवहार करना चाहिए।कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।वक्त बदलते देर नहीं लगती भाग्य किसी को भी अर्श पर ले जाता है और किसी को फर्श पर ले जाता है इसलिए मानव को मर्यादा में रहकर ही हर काम करना चाहिए।आदमी को किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए।किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाता तो फिर से कायम कर पाना मुश्किल हो जाता है।ऐसे मानव का जीवन व्यर्थ है जो दूसरों को दुख देता है।गरीब आदमी को कभी नहीं सताना चाहिए अगर गरीब की बददुआ लग जाए तो बड़े से बड़ा धराशायी हो जाता है इसलिए हर मानव को हमेशा मानव के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए।मानव को ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी उसे सदियों तक एक अच्छे इन्सान के .प में हमेशा याद किया जा सके। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए।आज का मानव पैसों से बैंक के खातों को तो भर रहा है मगर उपर का खाता खाली है इसलिए प्रत्येक साधन-संपन्न मानव को लाचार व गरीब लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। मानव को एकजुट होकर हर मानव का काम करना चाहिए, कहते है कि एकता में बड़ा बल होता है।प्रत्येक मानव को पता है कि एक दिन सबको मौत आनी है तो फिर मानव क्यों नहीं समझ रहा है।मानव जब कोई चीज बनाता है तो वह उसकी गारंटी तय करता है मगर उसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है कि कब प्राण निकल जाएं।रात दिन अवैध तरीकों से जायदाद जोड़ रहा है मगर किसके लिए आज तक कोई उठा कर नहीं लेकर गया तो फिर यह मोह माया क्यों है।मानव को नीच कर्मो को छोड़ देना चाहिए अच्छे कर्म करने चाहिए।प्रतिभा किसी की मोहताज़ नहीं होती प्रतिभा कभी झुकने नहीं देती. प्रतिभायें शिखर पर जरूर पहुंचाती है .कहते है कि हाथ से छिना जा सकता है मगर भाग्य को नहीं छिना जा सकता। जो भाग्य में है वह ज. र मिलेगा।देर ज. र है मगर सच ही पुरस्कृत होता है। सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए सच्चाई की हमेशा जीत होती है . सच कभी नहीं हारता . सच्चा मित्र वही होता है जो कभी भेदभाव नहीं करता मित्र गलत भी हो तब भी साथ नहीं छोड़ता .एक विचारक ने कहा था की दोस्ती बराबर की होनी चाहिए अगर दोस्ती बराबर की न हो तो टूट जाती है . आजकल दोस्ती हैसियत देखकर की जाती है की उसका जीवन स्तर कितना ऊँचा है स्टेटस क्या है क्या जॉब करता है क्या उसके पास गाड़ी है बंगला है आलीशान मकान है यह दोस्ती का पैमाना है . ग़रीब अमीर की दोस्ती बहुत कम होती है क्यूंकि अमीर अपनी पैसे की धौंस जमाते है और गरीबों को दबाते हैं इग्नोर करते हैं और नीचा दिखाते हैं .कहते हैं सच्चे व पक्के दोस्त नसीब वालों को ही मिलते हैं आज सच्चे मित्र मिलना बहुत ही कठिन है .वास्तव में सच्चा मित्र वह होता है जो हमेशा हर दु:ख सुख व मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहता है . दु:ख सदा नहीं रहते .सुख दु:ख जीवन की धूप छावं होते हैं और जीवन में इनका आना जाना एक सतत प्रक्रिया है . जीवन मे एक ही मित्र काफ़ी होता है जो हर संकट मे कंधे से कंधा मिला कर चले और कहे दोस्त कोई बात नहीं मै हूँ न घबराओ मत अंतिम सांस तक साथ निभाउंगा . आधुनिक इंटरनेट युग में ऐसे दोस्त विलुप्त हो चुके हैं . आज मतलबी दोस्त हो गए हैं मतलब खत्म दोस्ती खत्म हो जाती है . दोस्ती निस्वार्थ होनी चाहिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए . अक्सर देखा गया है की आज मतलबी दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे उदाहारण बहुत हैं की जो लोग कभी सच्चे दोस्त थे आज अच्छी जॉब पर लग गए तो अपने दोस्तों को भूल गए और पहचानने से इंकार करते हैं लेकिन इतिहास साक्षी है की जो अपनी औकात भूल जाते हैं वक़्त उनको तहस नहस कर देता है . नए नए दोस्त जब बन जाते हैं तो पुराने दोस्त भुला दिए जाते हैं एक शायर ने कहा था की जिंदगी में हर चीज अच्छी होती है लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे होते हैं जो हर परिस्थिति से वाकिफ होते हैं . नए दोस्त सिर्फ नौ दिन चलते हैं जबकि पुराने ताउम्र चलते हैं . आज कुछ लोग अमीर बन गए तो पुराने दोस्तों को अनदेखा करते हैं अपना समय भूल गए हैं . गरीब के साथ रिश्ता छुपाते हैं . गरीब का स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है वह स्वाभिमान से जीता है किसी को इग्नोर नहीं करता दिन रात बिना स्वार्थ के तत्पर रहता है लेकिन लोग उसका आदर नहीं करते . गरीब आदमी बेईमान नहीं होता नमक से खा लेता है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता .

जो नहीं है उसे पाना हो ध्येय

असंतुष्ट होने का अर्थ दुखी होना नहीं है। असल में कोई आदमी पूरी तरह सुखी होकर भी असंतुष्ट हो सकता है। सुखी होने का मतलब है, जो है, उसे आनंद से भोगना। और असंतुष्ट होने का अर्थ है- जो नहीं है उसे आनंद से पैदा करने का श्रम करना। जब अधिकतम लोग समाज में इस भांति श्रम करते हैं तो समाज संपन्न और समृद्ध होता है। और जब अधिक लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है बस ठीक है, वही रुक जाना है, तो फिर पूरा समाज धीरे-धीरे दरिद्र हो जाता है। जिंदगी का सारा विकास, जो नहीं है, उसे पाने से ही होता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि ऐसा किसी जगह मानने की जरूरत नहीं है कि अब सब पूरा हो गया, अब भला मुझे क्या करना है! यह मरने के ढंग हैं। यह अपने भीतर जिंदा रहते हुए मर जाना है।

जब तक श्वास है, तब तक एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि मेरी तो सच में ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो गईं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को दूसरों की आवश्यकताएं पूरा करने में लग जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पक्का ऐसा लगता है कि मेरी तो सभी आवश्यकताएं पूरी हो गईं, मैं क्यों श्रम करूं? तो उसे चारों तरफ देखना चाहिए कि अब मेरा काम तो जमीन पर खत्म हो गया, लेकिन दूसरों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, उनके लिए मैं श्रम करने में लग जाऊं।

लेकिन श्रम से नहीं बचा जा सकता। आपकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, तो अपने चारों तरफ देखिए। बहुत लोगों की पूरी नहीं हुई हैं, अत- उनके लिए श्रम करने में लग जाइए। लेकिन खाली बैठने का हक किसी को नहीं है। संन्यासी को भी खाली बैठने का हक नहीं है। देश को संपन्न करना है तो सभी को श्रम में लगना ही चाहिए। और श्रम में हम तभी लगेंगे जब कोई आवश्यकता पूरी करनी हो। चाहे अपनी, चाहे किसी दूसरे की, लेकिन आवश्यकता पूरी करने की दौड़ जारी रहनी चाहिए। यह दौड़ शांत हो, यह दौड़ आनंदपूर्ण हो, इतना मैं कहूंगा। यह दौड़ पागल की नहीं होनी चाहिए, विक्षिप्त की नहीं होनी चाहिए। यह दौड़ नींद को हराम कर देने वाली नहीं होनी चाहिए। यह दौड़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आदमी बिल्कुल होश खो दे और दौड़ता रहे, और उसे पता भी न हो कि कहां दौड़ रहा है। यह दौड़ बहुत आनंदपूर्ण होनी चाहिए, यह दौड़ बहुत शांत होनी चाहिए, यह दौड़ बहुत स्वस्थ होनी चाहिए। यह हो सकती है। लेकिन हमने इस तरफ सोचा नहीं

विचार मंथन

विपक्षी दलों के 300 सांसदों का पार्लियामेंट से चुनाव आयोग तक मार्च

(लेखक- सनत जैन)

11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक जाने के लिए 300 सांसदों ने एक साथ मार्च किया इन सांसदों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इन्हें लगभग 2 घंटे तक पार्लियामेंट थाने में रोक कर रखा गया। इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं, इसके बारे में अभी कोई बात सामने नहीं आई है क्योंकि यह पुलिस से बिना परमिशन लिए समूह में चुनाव आयोग तक जा रहे थे। कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा इन्हें कुछ देर हिरासत में लिया गया। बाद में छोड़ दिया गया तो उसका असर अलग होगा, यदि कोई मुकदमा दर्ज किया होगा तो आगे चलकर या एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी विपक्षी दलों के नेता और सांसद इस मार्च में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव ने बैरिकेट्स के ऊपर चढ़कर आगे जाने का प्रयास किया। महिला सांसदों ने भी बेरीकेट में चढ़कर विरोध दर्ज कराया। दो महिला सांसद बेहोश भी हो गईं। विपक्षी दलों के सांसदों का जो आक्रामक रुख था वह सरकार के लिए आगे चलकर परेशानी बढ़ाने का कारण बन सकता है। बिहार की एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो रही है। इसके खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने का मौका सरकार ने दे दिया है। सांसद अब संसद की बजाय सड़क पर उतरकर आ रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में केंद्रीय चुनाव आयोग और भाजपा दोनों की ही मुसीबतें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वोट बढ़ाए गए थे 8 से 10 फ़ीसदी वोट बढ़ाकर अंतिम समय पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी। कर्नाटक के एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र का जो खुलासा राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट के आधार पर किया है उससे स्पष्ट है, चुनाव के दौरान भाजपा और चुनाव आयोग की मिली-भगत से चुनाव में बहुत सारी अनियमितता की गई है। विपक्ष ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। 25 से लेकर 80 सीटों के बीच यह गड़बड़ी हुई है। विपक्षी दल के सांसद चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें देने से इंनकार कर दिया है। रातों-रात कानून बदल दिया गया, कि 45 दिन के बाद सारा डाटा नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद से केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर संपूर्ण देश में सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में जो एसआईआर हो रही है उसमें 65 लाख लोगों के नाम काटने की बात खुद चुनाव आयोग द्वारा की गई है। बिहार का चुनाव वोट काटकर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। मुसलमान और एससी/एसटी और गरीब लोगों के वोट काटकर चुनाव जीतने की जो रणनीति बनाई जा रही है उसको विपक्ष ने अब अच्छी तरह से समझ लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जो प्रारूप प्रदर्शित किया गया है उसे वोटर लिस्ट में कई तरीके की गड़बड़ियां पाई गई हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग कोई भी डाटा सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उसने यह लिखकर दे दिया है।

उसके बाद से केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर केवल भारत में ही नहीं दुनियाभर में सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, राइटर और अल जजीरा जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इसे लगातार कवर किया जा रहा है। विपक्ष के प्रति लगातार सहानुभूति और लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के पक्ष में सहानुभूति की लहर देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अब तो लोग न्यायपालिका के ऊपर भी वह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो पहले करते थे। अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीन सुनवाई हुई हैं। तीनों बार उसके जज बदले गए हैं। इसको लेकर भी अब आम लोगों के बीच में यह कहा जाने लगा है, कि तारीख पर तारीख और समय पर फैसला नहीं करके सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग को बचाने का काम कर रही है। विपक्ष भी अब संविधान को बचाने की बात कर रहा है।

विपक्ष का आरोप है कि जब केंद्रीय चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से चुनाव होंगे जो सीट वो जीतना चाहते हैं वह सुनियोजित रूप से प्लानिंग करके जीतेंगे। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पूरी तरह से खत्म हो गई है। नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब वही सरकार बनेगी जो चुनाव आयोग और सरकार मिलकर तय कर लेंगे। अब तो चुनाव के पहले ही सीटों का दावा कर लिया जाता है। 2047 तक केंद्र में भाजपा की सरकार रहेगी यह दावा सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता करते हैं। विपक्ष भी अब यह मानकर चल रहा है कि जिस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं ऐसी स्थिति में वह जब तक चाहेंगे सरकार में बने रहेंगे। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सड़कों पर लड़ाई देखने को मिल रही है।

एक बार फिर 1975 में जिस तरह से छात्र आंदोलन के माध्यम से सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था लगभग वही स्थिति अब बनती हुई दिख रही है। केंद्र सरकार एक साथ कई मोर्चा पर लड़ रही है। आगे चलकर क्या हालात होंगे कहना मुश्किल है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आरबीआई ने दी सफाई, खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र

- अच्छी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार

महेसाणा । गुजरात के महेसाणा में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस तय करना पूरी तरह बैंकों का अधिकार है। यह निर्णय आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने कहा कि बैंक अपनी नीति और व्यावसायिक रणनीति के आधार पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बचत खातों में 50,000 तक का न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य कर दिया है। वहीं कुछ बैंक 10,000, 2,000 या इससे भी कम न्यूनतम बैलेंस की सीमा निर्धारित करते हैं। कुछ बैंक ग्राहकों को इस बाध्यता से पूरी तरह मुक्त भी कर चुके हैं। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि अच्छी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक ÷शुभ शुरुआत÷ बताते हुए कहा कि यह योजना आर्थिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत खाताधारकों को दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और अटल पेंशन योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जिनका हर व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर घटाकर 3.6 प्रतिशत की

मेलबर्न । ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती करते हुए इसे 3.85 फीसदी से घटाकर 3.6 फीसदी कर दिया। यह इस वर्ष की तीसरी कटौती है, इससे पहले फरवरी और मई में भी दरों में इतनी ही कमी की गई थी। नई दर मार्च 2023 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। इस फैसले के पीछे दो प्रमुख कारण हैं, मुद्रास्फीति में गिरावट और आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का यह कदम व्यापक रूप से अपेक्षित था, क्योंकि महंगाई में लगातार कमी आ रही है और उपभोग में गिरावट देखी जा रही है। इस कटौती से कर्ज लेना सस्ता होगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ सकती है, लेकिन बचत पर ब्याज दर घटने की संभावना है। बैंक की यह नीति देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

एसआईपी में निवेश जुलाई में 28,000 करोड़ के पार

नई दिल्ली । भारतीय म्युचुअल फंड उद्योग में व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के ताजा आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 में एसआईपी के जरिए 28,464 करोड़ का निवेश हुआ, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। जून में यह आंकड़ा 27,000 करोड़ से ऊपर था, यानी लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड निवेश दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि भारतीय निवेशकों की बढ़ती परिपक्वता, वित्तीय जागरूकता, डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म्स की पहुंच और शेयर बाजार में भरोसे के कारण संभव हो सकी है।

एप्पल एआई इंडस्ट्री में खेल रहा राजनीति, मस्क करेंगे कंपनी पर कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली।

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एप्पल से कहा है कि उनकी एआई कंपनी एक्सएआई जल्द ही एप्पल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। मस्क का आरोप है कि ऐपल इस तरह से व्यवहार कर रही है जिससे ओपनएआई के अलावा कोई भी एआई कंपनी ऐप स्टोर में नंबर वन पर नहीं पहुंच सकती। यह विवाद तब बढ़ा जब एक्स, ऐप स्टोर की न्यूज कैटेगरी में नंबर वन और टॉप फ्री ऐप्स की सूची में पांचवें स्थान पर पहुंच गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने सवाल उठाया कि एप्पल ने न तो एक्स और न ही ग्रोक को अपने ÷मस्ट हैव÷ सेक्शन में शामिल किया है। उन्होंने पूछा कि क्या आप राजनीति खेल रहे हैं? मामला क्या है? जानने की इच्छा है। मस्क ने यह भी कहा कि एप्पल ने सिर्फ तराजू पर अंगूठा नहीं रखा, बल्कि पूरा शरीर रख दिया है। मस्क ने एक्स पर लिखा कि एप्पल ऐसा व्यवहार कर रही है जिससे ओपनएआई के अलावा कोई भी एआई कंपनी ऐप स्टोर में शीर्ष स्थान नहीं हासिल कर सकती। यह साफ तौर पर एंटी-ट्रस्ट कानून का उल्लंघन है। एक्सएआई इस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करेगी। एप्पल और मस्क के बीच यह नया विवाद टेक इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा, बाजार में प्रभुत्व और एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।

बता दें जून 2024 में एप्पल ने ऐलान किया था कि वह ओपनएआई के साथ साझेदारी कर चेटजीपीटी को अपने सभी डिवाइसों में इंटीग्रेट करेगी। उस समय ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा था। हम के साथ मिलकर चेटजीपीटी को यूजर्स तक नए तरीके से पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं। यह साझेदारी सुरक्षा, नवाचार और एआई को सभी के लिए सुलभ बनाने के हमारे मिशन के अनुरूप है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था एप्पल अगले चार सालों में अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मंगलवार को 10 पैसे की बढ़त के साथ ही 87.63 पर बंद हुआ। वहीं गत दिवस रुपया 87.73 पर बंद हुआ था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 87.70 पर खुला और फिर बढ़त दर्ज करते हुए 87.65 के स्तर तक गया, जो पिछले सत्र के 87.75 के मुकाबले सुधार को दर्शाता है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार रुपये में मजबूती का कारण घरेलू शेयर बाजारों में तेजी है। हालांकि, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार शुल्क को लेकर जारी अनिश्चितता और वैश्विक आर्थिक चिंताओं के कारण बाजार में सतर्कता बनी हुई है। निवेशक अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जो मुद्रास्फीति के रुझान और भविष्य की मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं।

शेयर बाजार में महिला निवेशकों की भागीदारी बढ़ी

- 30 साल से कम उम्र के निवेशक घटे

नई दिल्ली ।

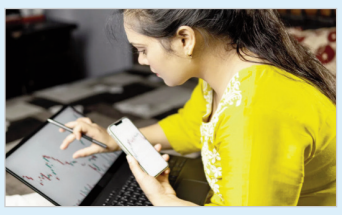

देश में शेयर बाजार में महिला निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी राज्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। इसके विपरीत, 30 साल से कम उम्र के निवेशकों का अनुपात घटा है, जो बाजार में युवाओं की कम भागीदारी को दर्शाता है। महाराष्ट्र में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 28.4 फीसदी पर पहुंच गई है, जो वित्त वर्ष 2023 में 25.6 फीसदी थी। गुजरात दूसरे स्थान पर है, जहां यह आंकड़ा 26.6 फीसदी से बढ़कर 27.8 फीसदी हो गया है। देश के दूसरे सबसे बड़े निवेशक आधार वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी महिला निवेशकों की संख्या बढ़कर 18.7 फीसदी हो गई है, जबकि यह राष्ट्रीय औसत 24.5 फीसदपी से कम है। फिर भी, यह वित्त वर्ष 2023 के 16.9 फीसदी से बेहतर स्थिति है। छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। गोवा सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद मिजोरम, चंडीगढ़, दिल्ली और सिक्किम का स्थान है। वहीं युवा निवेशकों की हिस्सेदारी में कमी देखी गई है। मार्च 2024 में 30 साल से कम उम्र के निवेशकों की हिस्सेदारी 40 फीसदी थी, जो जून 2025 तक घटकर 39 फीसदी रह गई है। यह गिरावट नए युवा निवेशकों के कम प्रवेश के कारण हुई है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बैंकिंग सहित कई क्षेत्रों में बिकवाली हावी रहने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 368.49 अंक टूटकर 80,235.59 और 50 शेयरों पर आधारित निफ्टी 97.65 अंक नीचे आकर 24,487.40 पर बंद हुआ। इसके साथ ही वित्तीय सर्विसेज इंडेक्स एक फीसदी से अधिक नीचे आया। वहीं एफएमसीजी, रियल्टी, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा इंडेक्स बढ़कर बंद हुए।

वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप में मिश्रित रुख रहा। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 154.15 अंक गिरकर 56,324.85 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 6.40 अंक बढ़कर 17,498.10 पर आ गया। सेंसेक्स पैक में मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, एमएंडएम, एनटीपीसी, टाटा स्टील, टाइटन, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी और एचसीएल टेक के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, इटरनल और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।

वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाद में आईटी शेयरों की मजबूती के चलते शेयर बाजार में तेजी लौटी। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर जारी अनिश्चितता ने निवेशकों को सतर्क बनाए रखा है। इसके चलते बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल` देखा जा रहा है। बीएसई सेंसेक्स 100 अंकों की गिरावट के साथ 80,508 पर खुला, जबकि निफ्टी50 ने भी कमजोरी के साथ शुरुआत की। शुरुआत में सेंसेक्स 276 अंक चढ़कर 80,880 पर पहुंच गया और निफ्टी भी 89.70 अंक बढ़कर 24,674 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई बाजारों की बात करें तो चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के बाजारों में भी तेजी रही। वहीं अमेरिका के प्रमुख सूचकांक सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि निवेशक सीपीआई डेटा का इंतजार कर रहे हैं। डाउ जोन्स, एसएंडपी 500 और नैस्डैक में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को ट्रंप ने 90 दिनों के लिए बढ़ाया

- अब अमेरिका और चीन को अपने व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने मिल गया अतिरिक्त समय

वाशिंगटन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ चल रहे व्यापारिक समझौते की समय सीमा को 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब यह समझौता मंगलवार देर रात समाप्त होने वाला था। अगर यह समय सीमा खत्म हो जाती, तो अमेरिका चीन से आयात पर पहले से लग रहे 30 प्रतिशत शुल्क को और बढ़ा सकता था, जिससे चीन की ओर से भी जवाबी करों की आशंका थी। इस टकराव से वैश्विक बाजारों में भारी अस्थिरता आ सकती थी। ट्रंप ने इस विस्तार की जानकारी अपने सोशल मीडिया मंच पर दी और कहा कि उन्होंने इसके लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौते की बाकी शर्तें यथावत रहेंगी। इस विस्तार से अब अमेरिका और चीन को अपने व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इस कदम का अमेरिकी कारोबार जगत ने स्वागत किया है। अमेरिका-चीन व्यापार परिषद के अध्यक्ष सीन स्टीन ने कहा कि इससे दोनों देशों को बातचीत का अवसर मिलेगा, जो दीर्घकालिक व्यापारिक स्थिरता के लिए अहम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे अमेरिकी

कंपनियों को चीन में बाज़ार पहुंच बढ़ाने और व्यापारिक योजनाएं बनाने में भरोसा मिलेगा। इस निर्णय ने न सिर्फ एक बड़े आर्थिक टकराव को टाल दिया है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि वर्ष के अंत तक ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच एक उच्च स्तरीय शिखर बैठक हो सकती है।

खरीफ सीजन में धान की बुवाई में 12 फीसदी की बढ़ोतरी

नई दिल्ली । चालू खरीफ सत्र 2025 में देशभर में फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में तेज गति से हो रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा 8 अगस्त तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, धान की बुवाई इस वर्ष अब तक 12 प्रतिशत बढ़कर 364.80 लाख हेक्टेयर पहुंच गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक यह आंकड़ा 325.36 लाख हेक्टेयर था। खरीफ मौसम में कुल बुवाई क्षेत्र बढ़कर 995.63 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 38.48 लाख हेक्टेयर अधिक है। इसमें मुख्य रूप से धान, मोटे अनाज और गन्ने की बुवाई में इजाफा हुआ है। मोटे अनाजों की बुवाई 170.96 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 178.73 लाख हेक्टेयर हो गई है, जबकि गन्ने की बुवाई 55.68 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 57.31 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई है। दलहन क्षेत्र में मामूली वृद्धि हुई है, जो अब 106.68 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। हालांकि, कुछ फसलों में गिरावट भी देखी गई है। तिलहन की बुवाई 182.43 लाख हेक्टेयर से घटकर 175.61 लाख हेक्टेयर रह गई, वहीं कपास का रकबा भी घटकर 106.96 लाख हेक्टेयर हो गया है।भारतीय मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है, जिससे आगामी हफ्तों में फसलों की बुवाई और उत्पादन में और सुधार की उम्मीद है।

देश की आईटी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 24 फीसदी तक गिरा

- निवेशक आईटी सेक्टर की जगह अन्य क्षेत्रों में दे रहे हैं निवेश करने में प्राथमिकता

नई दिल्ली ।

भारत की प्रमुख सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा कंपनियों का प्रदर्शन कमजोर होने के कारण निवेशक उनसे दूरी बना रहे हैं। 2025 की शुरुआत से देश की टॉप आईटी कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण लगभग 24 फीसदी घट गया है। आय में सुस्ती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर जोखिम की बढ़ती चिंता के चलते आईटी सेक्टर में निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। बीएसई सेंसेक्स में शामिल टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे शीर्ष पांच आईटी कंपनियों का पीई मल्टीपल दिसंबर 2024 के 25.5 गुना से घटकर 22.3 गुना रह गया है, जो पिछले पांच साल के निचले स्तर पर है। यह पहली बार है जब आईटी सेक्टर बीएसई सेंसेक्स के कुल पीई मल्टीपल से नीचे कारोबार कर रहा है। जबकि बीएसई सेंसेक्स ने 2024 के अंत से 2.2 फीसदी की बढ़त दर्ज की है। टीसीएस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसका बाजार पूंजीकरण इस साल अब तक 26 फीसदी तक गिर चुका है। इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 24.3 फीसदी, एचसीएल टेक का 23.1 फीसदी, विप्रो का 20.7 फीसदी घटा है। टेक महिंद्रा का प्रदर्शन बेहतर रहा, जिसका बाजार पूंजीकरण केवल 13.2 फीसदी कम हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि आईटी कंपनियों की आय में सुस्ती और निवेशकों का दूसरे क्षेत्रों की ओर रुख इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं। साथ ही एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर अनिश्चितता भी निवेशकों को सताती है। फिलहाल, निवेशक आईटी सेक्टर की जगह अन्य क्षेत्रों में निवेश करना प्राथमिकता दे रहे हैं।

एयर इंडिया की दिल्ली- वॉशिंगटन डी.सी. सीधी उड़ान सेवा 1 सितंबर से बंद

नई दिल्ली ।

एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली और अमेरिका के वॉशिंगटन डी.सी. के बीच चलने वाली सीधी उड़ान सेवा बंद करने का बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने यह कदम अपनी बाकी उड़ानों को बेहतर और समय पर चलाने के उद्देश्य से उठाया है। एयर इंडिया ने इस फैसले के पीछे कई कारण बताए हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि कंपनी अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों को आधुनिक बनाने के लिए 'रीट्रोफिट प्रोग्राम' चला रही है। यह प्रक्रिया 2026 के अंत तक चलेगी, जिसके दौरान कई विमान एक साथ सेवा से बाहर रहेंगे। इस वजह से उड़ानों के लिए उपलब्ध विमानों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए कंपनी ने दिल्ली- वॉशिंगटन सीधी उड़ान सेवा रोकने का फैसला किया है ताकि अन्य उड़ानों को प्रभावित न होने दिया जा सके। दूसरा कारण पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का अक्सर बंद रहना है। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने से भारत से अमेरिका जाने वाली उड़ानों को लंबा

रूट लेना पड़ता है। इससे यात्रा का समय बढ़ जाता है और खर्च भी बढ़ जाता है। यह भी इस फैसले में एक महत्वपूर्ण वजह है। यात्रियों के लिए यह फैसला थोड़ी असुविधा पैदा कर सकता है। जिन यात्रियों ने 1 सितंबर के बाद के लिए दिल्ली-वॉशिंगटन की उड़ान का टिकट बुक किया है, उन्हें एयर इंडिया वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध कराएगी या टिकट की राशि वापस करेगी। कंपनी जल्द ही यात्रियों को इसके बारे में जानकारी देगी।

भारत में ऑटोमोटिव चिप निर्माण की दिशा में क्वालकॉम का बड़ा कदम

- कंपनी की रणनीति इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चिपसेट उत्पादन पर केंद्रित

नई दिल्ली ।

अमेरिका स्थित चिप डिज़ाइन कंपनी क्वालकॉम अब भारत में ऑटोमोटिव मॉड्यूल के निर्माण का स्थानीयकरण कर रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्वालकॉम अपने शीर्ष वैश्विक साझेदारों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थानांतरित करने में मदद कर रही है। इसका उद्देश्य भारत में ऑटोमोटिव सप्लाई चेन को मजबूत बनाना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के ऑटोमोटिव, औद्योगिक और एम्बेडेड आईटीओ के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि कंपनी भारतीय ऑटो कंपनियों को तकनीकी सहयोग देने के लिए भारी निवेश कर रही है। वर्तमान में कंपनी के कई मॉड्यूल चीन, कोरिया और ताइवान में बनते हैं, लेकिन अब भारत में ही निर्माण की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी की यह रणनीति विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चिपसेट उत्पादन पर केंद्रित है। क्वालकॉम पहले ही भारत की प्रमुख ऑटो कंपनियों टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और हुंदै के साथ साझेदारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि क्वालकॉम एक फैबलेस कंपनी है, यानी वह चिप्स डिज़ाइन करती है, लेकिन उनका निर्माण तीसरे पक्ष द्वारा

भारत का पवन ऊर्जा सेक्टर तेज़ विकास की ओर, सुज़लॉन को फायदा

नई दिल्ली।

भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र आगामी वर्षों में तेजी से बढ़ने वाला है। सरकार की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नीति, फैक्ट्री क्षमता में वृद्धि और नए प्रोजेक्ट्स के कारण 2030 तक पवन ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 51.6 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य है। अगले पांच वर्षों में लगभग 48.4 गीगावाट नई पवन ऊर्जा जोड़नी होगी, जिसमें से 25.5 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स पहले से काम में हैं और नई नीलामी से विकास और तेज होगा।

सरकार ने पवन टरबाइन के आवश्यक पार्ट्स का घरेलू उत्पादन अनिवार्य कर दिया है। ब्लेड, टावर और गियरबॉक्स तो देश में बनते हैं, लेकिन जेनरेटर और बियरिंग के लिए अभी भी कच्चा माल आयात करना पड़ता है। इससे छोटे आयात-निर्भर प्लेयर कम होंगे और बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। देश की टरबाइन निर्माण क्षमता 18 गीगावाट सालाना है, पर इसका मात्र 20-25 फीसदी ही उपयोग हो रहा है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे चीन पर कच्चे माल की निर्भरता, टेक्नोलॉजी रिसर्च की कमी और ट्रांसमिशन नेटवर्क में देरी। लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की ट्रांसमिशन प्लानिंग में तेजी आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सुज़लॉन एनर्जी इस क्षेत्र में सबसे मजबूत स्थिति में है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2026 में लगभग 4 गीगावाट के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिनमें 1.5 गीगावाट एनटीपीसी से होंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग नियमों से सुज़लॉन को लाभ होगा, क्योंकि उसके पास पूरी तरह एकीकृत उत्पादन सेटअप है। इसके कारण कंपनी का ऑर्डर बुक 6.5 गीगावाट तक पहुंच सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

शुभमन गिल बने जुलाई महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ, चौथी बार जीता यह पुरस्कार

दुबई (एजेंसी)। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड की स्पिनर सोफिया डंकले को क्रमशः जुलाई के लिए ढ्ढष्टष्ट पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। गिल को इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर वियान मुल्डर से कड़ी टक्कर के बाद प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। यह उनका चौथा प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान है, इससे पहले उन्होंने इस साल फरवरी, जनवरी और सितंबर 2023 में यह सम्मान जीता था।

इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने जुलाई में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन टेस्ट मैचों में 94.50 की शानदार औसत से 567 रन बनाए जिसमें छह मैचों में एक दोहरा शतक और दो शतक शामिल हैं। भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में यह गिल का पहला दौरा था और उन्होंने कहा कि यह सम्मान पाना उनके लिए एक बड़ा सम्मान है।

गिल ने कहा, 'जुलाई के लिए ढ्ढष्टष्ट प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने पर बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार यह और भी ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि यह पुरस्कार मुझे कप्तान के रूप में मेरी पहली टेस्ट सीरीज के दौरान मेरे प्रदर्शन के लिए मिला है। बर्मिंघम में लगाया गया दोहरा शतक निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा और यह मेरे इंग्लैंड दौरे के सबसे यादगार पलों में से एक होगा।'

उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज कप्तान के रूप में मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था और दोनों टीमों ने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किए, जिन्हें दोनों टीमों के खिलाड़ी लंबे समय तक याद रखेंगे। मैं इस पुरस्कार के लिए मुझे चुनने के लिए जूरी का और इस रोमांचक सीरीज के दौरान मेरे साथ रहे मेरे साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।' गिल ने कहा, 'मैं आने वाले सीजन में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखने और देश के लिए और भी सम्मान लाने के लिए उत्सुक हूं।'

इस बीच सोफिया डंकले के बल्ले से लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें पहली बार आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिलाया है। उन्होंने इस मासिक पुरस्कार के लिए इंग्लैंड की साथी सोफी एक्लेस्टोन और आयरलैंड की कप्तान गैबी लुईस को कड़ी टक्कर दी। 27 वर्षीय खिलाड़ी ने ब्रिस्टल में भारत के खिलाफ दूसरे टी20आई में महीने की शुरुआत अच्छी नहीं की थी। हालांकि उन्होंने अगले मैच में शानदार वापसी की और 53 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी क्लास का प्रदर्शन किया, यह पारी इंग्लैंड की छह रनों की मामूली जीत में अहम साबित हुई।

डंकले ने चार टी20आई मैचों में 36 की औसत से 144 रन बनाए, जिसमें 134.57 की प्रभावशाली स्ट्राइक रेट रही। उनका यह फॉर्म वनडे में भी जारी रहा, जहां उन्होंने 63 की औसत और 91.97 के स्ट्राइक रेट से 126 रन बनाए। फॉर्म में चल रही इंग्लैंड की इस बल्लेबाज के लिए बल्ले से एक मजबूत ऑलराउंड महीने का समापन हुआ। पुरस्कार

जीतने पर डंकले ने कहा, 'भारत के खिलाफ एक बेहद कड़ी सीरीज के बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतकर मैं बेहद खुश हूं। हम यह सीरीज जीतना पसंद करते, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीसी महिला विश्व कप की ओर बढ़ते हुए हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। भारत अपनी जीत का हकदार था और इस सीरीज का हिस्सा बनना एक शानदार अनुभव था।'

दीप्ति शर्मा टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची, स्मृति मंधाना को हुआ नुकसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला टी20 की नवीनतम रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना बल्लेबाजों के बीच टॉप से दूसरे स्थान पर खिसक गईं।

दीप्ति पाकिस्तान की सादिया इकबाल के साथ 732 रेटिंग अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। सादिया रैंकिंग में पहले स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक गई जबकि ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड चार रेटिंग अंको की बढ़त के साथ पहली बार टॉप रैंकिंग की टी20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज बनने में सफ रही।

सदिया ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में सिर्फ तीन विकेट लेने के बाद रेटिंग अंक गवां दिए। पाकिस्तान महिला टीम इस सीरीज को 1-2 से हार गई थी। सदरलैंड ने मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट लेने के बाद से सबसे छोटे अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में कोई मैच नहीं खेला है। इससे उनके रेटिंग अंक में कोई बदलाव नहीं आया है।

टी20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दीप्ति 387 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई हैं। वह वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर से पीछे हैं।

वहीं बल्लेबाजों की लिस्ट में स्मृति मंधाना एक स्थान फिसल कर इंग्लैंड की नैट सिवर-ब्रंट के बाद दूसरे पायदान पर गई हैं। जबकि हरमनप्रीत कौर 10 पायदान की छलांग लगातार शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शामिल होने के करी पहुंच गई हैं। वह फिलहाल 11वें नंबर पर हैं।

वॉर्नर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवे खिलाड़ी बने

मैनचेस्टर (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने इंग्लैंड में जारी द हंड्रेड प्रतियोगिता के दौरान ओरिजिनल्स के खिलाफ अपनी टीम लंदन स्पिरिट्स की ओर से अर्धशतक लगाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब वार्नर टी20 क्रिकेट

में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवे खिलाड़ी बन गये हैं। इसी के साथ ही ही उन्होंने भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। अब 419 टी20 मैचों में वार्नर के 36.80 की औसत और 140 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 13,545 रन हो गये हैं। जिसमें 8 शतक और 113 अर्द्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 है। दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाज विराट ने 414 मैचों और 397 पारियों में 41.92 की औसत, 134.67 की स्ट्राइक रेट, 9 शतक और 105 अर्द्धशतकों के साथ 13,543 रन बनाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122 है। टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वेस्टइंडीज के क्रिस गेल हैं जिन्होंने 463 मैच खेले हैं जिनमें 455 पारियों में 36.22 की औसत, 144.75 की स्ट्राइक रेट, 22 शतक और 88 अर्द्धशतक के साथ 14,562 रन बनाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रहा है।

यह वार्नर का पहला द हंड्रेड सीजन है और वह तीन मैचों में 75.00 की औसत, 141.50 की स्ट्राइक रेट और दो अर्धशतकों के साथ 150 रन बनाकर शीर्ष रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

मैच की बात करें तो मैच के दौरान वॉर्नर ने 51 गेंदों में 12 चौकों और एक छक्के की मदद से 71 रनों की शानदार पारी खेली और 139 से ज्यादा की औसत से रन बनाए। हालांकि इसके बाद भी उनकी टीम मैनचेस्टर द्वारा बनाए गए 164 रनों के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पायी।

उन्होंने 'गलत प्रारूप' से संन्यास लिया, रोहित-विराट के टेस्ट क्रिकेट छोड़ने पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली ~ रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के जल्द ही वनडे से संन्यास लेने की मीडिया रिपोर्टों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि भारतीय दिग्गजों ने गलत प्रारूप से संन्यास लिया और वर्तमान समय में वनडे क्रिकेट के अभाव के कारण उन्हें टेस्ट क्रिकेट की बजाय 50 ओवर के प्रारूप को छोड़ना चाहिए था।

कप्तान शुभमन गिल द्वारा भारत को 2-2 से शानदार ड्रॉ दिलाने के कुछ दिनों बाद ऐसी खबरें आने लगीं कि रोहित और विराट वनडे भी छोड़ सकते हैं। दोनों ही 2027 में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की योजना में नहीं हैं, जब तक कि दोनों अपनी मैच फिटनेस और फॉर्म साबित करने के लिए घरेलू 50 ओवर का क्रिकेट नहीं खेलते। दोनों क्रिकेटरों ने मई में भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी।

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए चोपड़ा ने कहा, %सच्चाई यह है कि उन्होंने गलत फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 छोड़ दिया था, लेकिन अगर वे टेस्ट खेलना जारी रखते और वनडे को अलविदा कह देते तो कहानी कुछ और होती। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 12 महीनों में भारत ने सिर्फ 6 वनडे खेले थे।'

उन्होंने आगे कहा, 'हो सकता है कि आप साल में

सिर्फ छह टेस्ट खेलें, लेकिन अगर ये सिर्फ छह टेस्ट भी हैं, तो ये 30 दिन का क्रिकेट है। अगर सिर्फ छह वनडे खेले जाते हैं, तो ये एक समयावधि में सिर्फ छह दिन का क्रिकेट होगा। आपके आखिरी ढ्ढक्क मैच से लेकर अगले वनडे मैच तक 100 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। आप बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। आप बिल्कुल भी अभ्यास नहीं कर रहे हैं।' चोपड़ा ने यह भी बताया कि इन दिनों वनडे सीरीज के बीच का अंतराल भी 'बेहद बड़ा' है और सिर्फ कुछ वनडे मैचों से फॉर्म, फिटनेस, डाइट के प्रति प्रतिबद्धता आदि को बनाए रखना मुश्किल होगा। मौजूदा कमेंटेटर ने कहा, 'तीन मैचों की एक सीरीज सात से आठ दिनों में खत्म हो जाती है। फिर अगली सीरीज तीन महीने बाद होगी। अंतराल बहुत बड़ा है और आप बीच में प्रथम श्रेणी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यह सच है कि अगर वे टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखते और वनडे छोड़ देते, तो लय में बने रहना बहुत आसान होता।' पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'जब आप टेस्ट से संन्यास ले चुके होते हैं और वनडे क्रिकेट ज्यादा नहीं खेला जाता, तो इसका कोई खास मतलब नहीं बनता। इसलिए सिर्फ दो महीने का तेज-तर्रार ढ्ढक्क, जहां आपको 14 से 16 पारियां खेलने को मिलेंगी और फिर छह महीने बाद तीन मैच और फिर तीन महीने बाद तीन मैच। मुझे लगता है कि यह बहुत, बहुत मुश्किल है।'

पिछले दो साल से शतक नहीं लगा पाये हैं बाबार

लाहौर । पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार असफल हो रहे हैं। वह पिछले दो साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं

लगा पाये हैं। उनके बल्ले से अंतिम शतक 30 अगस्त 2023 को निकला था। उसके बाद से ही वह कई अवसरों पर 50 के ऊपर तो पहुंचने में सफल रहे, मगर शतक नहीं लगा पाये हैं। बाबर आजम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाए 712 दिन और 71 पारियां हो गई है। बाबर आजम के करियर का यह दो शतकों के बीच सबसे लंबा अंतर है। इससे पहले 25वें शतक तक पहुंचने के लिए उन्हें 25 पारियां लगी थी, वहीं 8वां शतक उन्होंने 22 पारियों के बाद बनाया था। कई बार पाक क्रिकेटर उनकी तुलना भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली से करते रहे हैं। कोहली के करियर में भी एक खराब दौर आया था जब उनके बल्ले से भी शतक नहीं निकल रहे थे। विराट ने 2019 के बाद सीधा 2022 में शतक जड़ा था। उन्हें अपने 71वें अंतरराष्ट्रीय शतक के लिए 83 पारियां और 1020 दिनों का इंतजार करना पड़ा था। वहीं बाबर लगता है विराट कोहली को इस मामले में भी पीछे छोड़ने में लगे हैं।

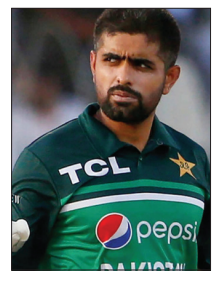

सैमसन आते हैं तो सीएसके में उनका स्वागत करुंगा :श्रीकांत

चेन्नई । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के श्रीकांत ने कहा है कि अगर संजू सैमसन चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) आते हैं तो उन्हें कप्तान बनाया जाना चाहिये। श्रीकांत के अनुसार सैमसन सीएसके में महेन्द्र सिंह धोनी के सबसे अच्छे उत्तराधिकारी बन सकते हैं। अभी सैमसन आईपीएल राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं। श्रीकांत का कहना है कि अगर रॉयल्स उन्हें रिलीज करता है तो मैं उनका सीएसके में स्वागत करुंगा।. उन्होंने कहा कहा, 'धोनी 44 साल के हैं और वह अपने अंतिम आईपीएल टूर्नामेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में टीम को उनके एक बेहतर विकल्प की जरुरत है और मेरा मानना

है कि इसके लिए सैमसन पहली पसंद हो सकते हैं।' उन्होंने कहा कि सैमसन तमिलनाडु में बेहद लोकप्रिय हैं जिससे भी टीम को प्रशंसकों को और अधिक समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही कौशल और ब्रांड वैल्यू के मामले में भी वह काफी आगे हैं। इसीलिए अगर उन्हें राजस्थान टीम छोड़ती है तो उन्हें लिया जाना चाहिये। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स से उन्हें रिलीज या ट्रेड करने का आग्रह किया है। वहीं रॉयल्स ने अभी तक इस मामले में . कोई बयान नहीं दिया है। आरआर के साथ सैमसन की यह दूसरी पारी थी। पहले 2013 से 2015 तक इस टीम के साथ थे। वहीं दूसरी पारी में वह साल 2018 से रॉयल्स के साथ जुड़े और 2022 से ही टीम की कप्तानी उनके पास है। सैमसन कप्तानी, विकेटकीपिंग के साथ ही सलामी बल्लेबाज के तौर पर अच्छे विकल्प हैं। तीनों ही भूमिकाओं में वह अपने को साबित करने में सफल रहे हैं। सीएसके को भी धोनी के बाद एक ऐसा खिलाड़ी चाहिये जो सभी भूमिकाएं कुशलता से निभा सके। ऐसे में सैमसन पर उसकी नजर है। सैमसन एक सलामी बल्लेबाज होने के साथ ही तेज गेंदबाजों के साथ–साथ स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। सैमसन के नाम 176 मैचों की 172 पारियों में 3 शतक और 26 अर्धशतक के साथ ही 4,704 रन बनाए हैं।

खेल विधेयक के समर्थन में उतरीं पीटी उषा, कहा- गतिरोध होगा खत्म

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा की मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को अपना स्पष्ट समर्थन देते हुए कहा कि ये दशकों से चली आ रही स्थिर यथास्थिति को समाप्त करने में सहायक होगा। इसके अलावा देश के खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लएगा। बता दें कि, ये विधेय लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया।

दरअसल, सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित विधेयक पर चर्चा के दौरान उषा ने इसके प्रावधानों की सराहना की। जिसें राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना भी शामिल है। जिसके बाद खेल महासंघों

(एनएसएफ) को मान्यता देने का सर्वोच्च अधिकार होगा। केंद्रीय निधि प्राप्त करने के लिए एनएसबी से संबद्धता अनिवार्य होगी।

बता दें कि, विधेयक में खेल विवादों से निपटने के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल को राष्ट्रीय खेल महासंघों के चुनावों की निगरानी का भी प्रस्ताव है। एक अन्य मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति के साथ बैठीं उषा ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि, आज का दिन व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे इस पल का लंबे समय से इंतज़ार था।

उन्होंने पिछले साल इस विधेयक का विरोधा किया था और इसे सरकारी हस्तक्षेप बताया था और चेतावनी दी थी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से प्रतिबंध का सामन करना पड़ा सकता है। हालांकि, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उन्होंने अपने विचार बदल दिए हैं।

स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड से की सगाई, जॉर्जिना ने शेयर की खुशखबरी

वाशिंगटन । स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लंबे समय से उनकी पार्टनर रही जॉर्जिना रोड्रिग्स ने सगाई कर ली है। जॉर्जिना 31 साल की हैं। उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपनी उंगली में एक बड़ी अंगूठी दिखाते हुए एक तस्वीर के साथ इस खुशखबरी की घोषणा की। जॉर्जिना ने तस्वीर के साथ स्पेनिश में कैप्शन में लिखा, 'हां हमने सगाई कर ली है। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है।' जॉर्जिना और 40 वर्षीय रोनाल्डो की दो बेटियां हैं। उन्होंने रोनाल्डो के अन्य तीन बच्चों की परवरिश में भी मदद की है। जॉर्जिना ने 2022 में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था लेकिन उनमें से एक लड़के की मौत हो गई थी। रोनाल्डो की जॉर्जिना से 2016 में मुलाकात हुई थी जब वह मैड्रिड के एक स्टोर में काम करती थीं। रियाल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड पूर्व स्टार रोनाल्डो अब सऊदी अरब में अल–नासर के लिए खेलते हैं।

सिनसिनाटी ओपन ~ आर्यना संबालेका ने जीता महिला सिंगल्स खिताब, फाइनल में एम्मा रादुकानु को हराया

सिनसिनाटी (एजेंसी)। दुनिया की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने 3 घंटे 9 मिनट तक चले सिनसिनाटी ओपन के संघर्षपूर्ण फाइनल में ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु को हराकर खिताब जीता। रादुकानु एक बार फिर से सबालेंका के खिलाफ लगातार हार के सिलसिले को तोड़ने में नाकामयाब रहीं।

पहले सेट में रादुकानु ने शानदार खेल दिखाया और पहले नौ अंक जीतकर जोरदार शुरुआत की। लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता गया, उनकी पकड़ कमजोर होती गयी। उनकी सर्विस कमजोर पड़ने लगी। वहीं, सबालेंका ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद दमदार वापसी की और टाई-ब्रेक में पहला

सेट 7-6 (3) से जीता। दूसरे सेट में एम्मा रादुकानु ने जोरदार वापसी की। उन्होंने सबालेंका को छकाते हुए सेट 4-6 से अपने नाम किया।

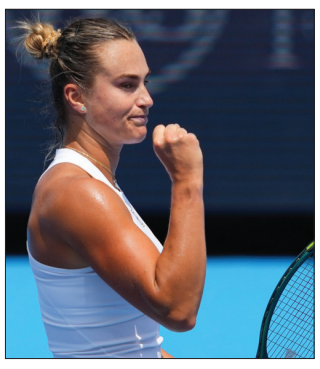

तीसरा सेट बेहद अहम और निर्णायक था। दोनों की तरफ से उनका सर्वश्रेष्ठ खेल देखने को मिला। रादुकानु ने ताकतवर फोरहैंड और बैकहैंड का इस्तेमाल किया और सबालेंका के आक्रमण को रोकने में भी सफलता पाई। वहीं नंबर वन खिलाड़ी सबालेंका ने भी अपनी क्लास से रादुकानु पर अपनी पकड़ बनाए रखी और सेट टाई ब्रेकर में 7-6 (5) से जीतकर खिताब अपने नाम किया।

जीत के बाद सबालेंका ने कहा, 'मैं इस मुश्किल मैच को जीतकर खुश हूं। रादुकानू पर तीसरे सेट में जीत हासिल करने के लिए मुझे जोखिम भरे शॉट खेलने पड़े। मुझे उसके खिलाफ लड़ने में मज़ा आ रहा है। वह एक अद्भुत खिलाड़ी है, एक बहुत अच्छी इंसान है, और मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। मैं उसे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ देखकर खुश हूं। वह खेल में लगातार सुधार कर रही है।'

एम्मा रादुकानु बेशक यह मैच नहीं जीत सकी, लेकिन उन्होंने अपने खेल से प्रभावित किया। फाइनल हारने के बाद रादुकानु ने कहा, ÷वह किसी खास वजह से नंबर 1 हैं। मैंने विंबलडन की तुलना में उन पर ज्यादा दबाव डाला। यह मेरे लिए संतोषजनक था। मैं हमेशा से सोचती थी कि घास मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है। अब भी यही मानती हूं। इसलिए हार्ड कोर्ट पर उन पर दबाव डालने पर मुझे बहुत गर्व है।'

बुमराह को एशिया कप के बाद दिया जा सकता है आराम

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के एशिया कप में खेलने को लेकर अभी तक साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। वहीं अब एक रिपोर्ट के अनुसार बुमराह को एशिया कप के लिए शामिल किया जा सकता है और इसके बाद उन्हें आराम दिया जा सकता है। एशिया कप अगले माह सितंबर में

खेला जाएगा। इसमें एशिया की 8 टीमें भाग लेंगी। भारत की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन 9 से 28 सितंबर के बीच दुबई और अबू धाबी में किया जाएगा। इसमें. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, यूएई और ओमान की टीमें खेलेंगी। बुमराह टी20 में भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पांचवे गेंदबाज हैं, उन्होंने अंतिम बार 2024 टी20 विश्व कप के फाइनल में खेला था। उनके नाम कुल 70 मैचों में 89 विकेट हैं। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वानर चयन समिति 19 या 20 अगस्त को एशिया कप के लिए भारतीय टीम का चयन कर सकती है। ये एनसीए की फिटनेस रिपोर्ट पर भी आधारित रहेगा। माना जा र हा है कि बुमराह को एशिया कप के बाद अक्टूबर की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज में आराम दिया जा सकता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 2 से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि दूसरा टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

सूर्यकुमार यादव सहित एशिया कप से बाहर हो सकता है ये खिलाड़ी, अय्यर ने पास किया फिटनेस टेस्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 के लिए टीम के चयन से पहले राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में नियमित फिटनेस मूल्यांकन से गुजरेंगे। यह मूल्यांकन 11 और 12 अगस्त को होगा क्योंकि यह स्टार खिलाड़ी पिछले कुछ समय से मुंबई में प्रशिक्षण ले रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रेयस अय्यर ने अपनी फिटनेस साबित कर दी है और सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वह निश्चित रूप से चयनकर्ताओं की पहली पसंद होंगे।

कप्तान सूर्यकुमार यादव हर्निया की सर्जरी से उबर नहीं पाए हैं और रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पूरी तरह से फिट होने के लिए NCA में एक और सप्ताह बिताने की आवश्यकता होगी, लेकिन इससे एशिया कप में उनके खेलने की संभावना कम है। इस बीच ACC ने घोषणा की है कि आगामी एशिया कप के दौरान भारत बनाम पाकिस्तान के दो प्रमुख मैच दुबई में होंगे, जो 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है।

भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में और एक बार फिर, संभवतः 21 सितंबर को इसी मैदान पर आमने-सामने होंगे। 29 सितंबर को होने वाला फाइनल भी दुबई में ही होगा। यह टूर्नामेंट अगले साल की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। यद्यपि कार्यक्रम 26 जुलाई को घोषित किए गए थे, लेकिन ACC ने आयोजन स्थलों की घोषणा नहीं की थी। टूर्नामेंट के 19 मैचों में से 11 दुबई में और 8 अबू धाबी में होंगे।

भारत अपने दो लीग मैच 10 सितंबर (UAE के खिलाफ) और 14 सितंबर (पाकिस्तान के खिलाफ) दुबई में खेलेगा जबकि ओमान के खिलाफ अंतिम लीग मैच 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा। सुपर सिक्स मैचों में अबू धाबी में केवल एक मैच निर्धारित है। भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई ग्रुप ए में हैं, जबकि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग ग्रुप बी में हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बच्चों को घर बैठे खेल-खेल में सिखाएं गणित के गुण

कोरोना महामारी के दौरान बच्चे अपने पाठ्यक्रम में से ऐसी विभिन्न कक्षाओं में दाखिला और भाग ले रहे हैं जो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उनके स्कूल द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह पैटर्न विभिन्न आयु समूहों में देखा गया है जिसके कारण भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ रही है।

कोरोना वायरस महामारी के बाद कई छात्र काफी मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए कई छात्र नए-नए हुनर सीख रहे हैं। ऐसे में भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग काफी बढ़ गई है। माता-पिता अपने बच्चों को नए कौशल सिखाने के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को गणित और सांख्यिकी गणना सिखाना चाहते हैं तो अबेकस ट्रेनिंग क्लास की मदद से आप अपने बच्चों को खेल में गणित पढ़ा सकते हैं।

कोरोना महामारी के दौरान बच्चे अपने पाठ्यक्रम में से ऐसी विभिन्न कक्षाओं में दाखिला और भाग ले रहे हैं जो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उनके स्कूल द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह पैटर्न विभिन्न आयु समूहों में देखा गया है जिसके कारण भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ रही है। माता-पिता अलग-अलग ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसके माध्यम से उनके बच्चों को रचनात्मक सीखने के माहौल में पाला जा सकता है। गणित और संख्या कुछ बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से आती है, लेकिन जब गणना की बात आती है तो स्कूल और कॉलेज के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा कुछ हद तक संघर्ष करता है। अबेकस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सदियों से मौजूद है और इसे अंकगणितीय कौशल और संख्यात्मक प्रवाह को विकसित करने के लिए दुनिया भर में सबसे अच्छे उपकरणों में से एक माना जाता है।

अबेकस टूल का उपयोग गणितीय कार्यों जैसे जोड़, घटाव, गुणा, वर्ग या घनमूल को करने के लिए किया जाता है। अबेकस का उपयोग दशमलव अंक, ऋणात्मक संख्या और बहुत कुछ गिनने के लिए भी किया जा सकता है। अपने गणना कौशल में सुधार के अलावा, अबेकस सीखने से बच्चे के समग्र विकास में मदद मिल सकती है। अबेकस सीखने के कुछ लाभ इस प्रकार हैं :

- कैलकुलेशन की गति और सटीकता में सुधार करता है
- विश्लेषणात्मक कौशल और तार्किक रीजनिंग का निर्माण करता है
- गणित में रुचि पैदा करता है
- एकाग्रता और अवलोकन शक्ति को बढ़ाता है
- मेमोरी में सुधार करता है
- आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान बनाता है

यहां भारत में पांच ऐसे प्लेटफार्मों के बारे में बताया गया है जो 100 प्रतिशत डिजिटल एबेकस प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और युवाओं को भविष्य के रोल मॉडल बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

ब्रिटिश यूथ इंटरनेशनल कॉलेज

यूके स्थित प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन अबेकस शिक्षण मंच लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। उनके मंच में पूरी तरह कार्यात्मक वर्चुअल अबेकस है जो बच्चों के समग्र मानसिक विकास के लिए इंटरैक्टिव प्रशिक्षक के नेतृत्व वाली अबेकस शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। ये ऑनलाइन कक्षाएं चरण-दर-चरण अप्रोच प्रदान करती हैं जिसका उद्देश्य छात्रों को अबेकस को ध्यान में रखकर मार्गदर्शन करना और कैलकुलेटर की तुलना में तेजी से संख्या की गणना करना है। शिक्षक प्रत्येक छात्र को गहन शिक्षण प्रदान करते हैं। वे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव जोड़, दशमलव घटाव, दशमलव गुणा और दशमलव भाग को कवर करते हैं। वे एकमात्र अबेकस कंपनी हैं जो दशमलव आधारित गणना प्रदान करती हैं।

उडेमी

उदमी अबेकस कोर्स का उद्देश्य आपकी गणना, क्षमता, संख्या बोध और मानसिक अंकगणित को बेहतर बनाने में मदद करके मस्तिष्क का विकास करना है। यह पाठ्यक्रम मल्टीमीडिया और एनिमेशन के जरिये आपको सिखाएगा कि अबेकस पर सही और तेज बुनियादी गणित संचालन कैसे करें। इन अबेकस ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू करके बच्चे अबेकस पर संख्याएं रखने, हल करने और जोड़ और घटाव को समझने में सक्षम होंगे।

अबेकस सुपरमैथ्स

'सुपरमैथ्स' छात्रों को अबेकस टूल का उपयोग करने के लिए एक दोस्ताना और इंटरैक्टिव मंच प्रदान करता है। उनकी कक्षाएं आपको ऑनलाइन वर्कशीट पर काम करके मानसिक सिद्धांत अवधारणाओं को अभ्यास में लाने की अनुमति देती हैं। यह कोर्स दो ट्रैक में आता है, जूनियर और सीनियर। पहले ट्रैक में 11 स्तर होते हैं जबकि दूसरे वरिष्ठ ट्रैक में 8 स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर के अंत में एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है जिसके बाद छात्र को अगले स्तर पर पदोन्नत किया जाता है। वे प्रशिक्षक के नेतृत्व में आवेदन आधारित वीडियो कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाते हैं।

अबेकस मास्टर

अबेकस मास्टर ने अबेकस को अधिक रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए अनूठी विशेषताओं के साथ एक व्यापक शिक्षण मंच बनाया है। यह ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म 5-12 वर्ष की आयु के बीच के छात्रों को अबेकस प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें आठ स्तर शामिल होते हैं जो बुनियादी से लेकर उन्नत अबेकस गणनाओं तक सभी विषयों को कवर करते हैं। छात्र इस पाठ्यक्रम को अपनी गति के हिसाब से ले सकते हैं; हालाँकि, पोर्टल पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए प्रत्येक स्तर पर कम से कम दो महीने बिताने का सुझाव देता है। उनकी कक्षाएं एनिमेशन, अंजान वीडियो और प्रैक्टिस वर्कशीट की मदद से दी जाती हैं।

स्मार्ट किड अबेकस

स्मार्ट किड की 'अबेकस फ्रेंचाइजी' बच्चों के लिए अबेकस ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करती है। ये कक्षाएं सप्ताह में एक बार 45 मिनट के लिए आयोजित की जाती हैं। समय में कोई पाबन्दी नहीं है और छात्र कई प्रकार के पाठ्यक्रमों में से चुन सकते हैं। यह आठ स्तरीय पाठ्यक्रम है जिसमें 5 बुनियादी और 3 अग्रिम स्तर हैं। पाठ्यक्रम 4-14 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये पाठ्यक्रम कौशल के विकास के साथ-साथ संपूर्ण मस्तिष्क विकास को बढ़ावा देते हैं।

वैकल्पिक चिकित्सा में कॅरियर बनाना चाहते हैं तो चुनें मैग्नेटिक थेरेपी

एक मैग्नेटो चिकित्सक को मैग्नेटोमीटर के सही उपयोग के बारे में पता होना चाहिए, जो एक चुंबक के ध्रुवों को निर्धारित करता है। इसके अलावा आपको चुंबकीय चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों की भी सही जानकारी होनी चाहिए।

मैग्नेटिक थेरेपी, जिसे मैग्नेट थेरेपी या मैग्नो थेरेपी भी कहा जाता है, वास्तव में एक वैकल्पिक चिकित्सा उपचार है, जिसमें विभिन्न रोगों के उपचार के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेहद सिंपल, इफेक्टिव, सुरक्षित व पूरी तरह से दर्दरहित प्राकृतिक उपचार है। चुंबकीय चिकित्सा को एक विज्ञान के साथ-साथ एक कला के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के विभिन्न अंगो, रोगों को जानने के साथ-साथ व मैग्नेट के उचित उपयोग को जानना भी उतना ही जरूरी है। विज्ञान में, चुंबकीय चिकित्सा एक्यूपंक्चर के समान है। वहीं कला में, इसमें विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न आकारों और शक्तियों के मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेहद डिफरेंट चिकित्सा थेरेपी है। तो चलिए जानते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे बनाएं कॅरियर-

स्किल्स

एक मैग्नेटो चिकित्सक को मैग्नेटोमीटर के सही उपयोग के बारे में पता होना चाहिए, जो एक चुंबक के ध्रुवों को निर्धारित करता है। इसके अलावा आपको चुंबकीय चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों की भी सही जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मानव शरीर व उसके महत्वपूर्ण अंगों की रचना व उसके विज्ञान के बारे में भी पता होना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता

भारत में केवल कुछ ही संस्थान मैग्नेट थैरेपी पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। मैग्नेट थेरेपी में सर्टिफकिट, डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10, 2 है और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक होना आवश्यक है। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 वर्ष की है और स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स 2 वर्ष का है। कुछ संस्थान शार्ट टर्म डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा कोर्स भी करवाते हैं, जिनकी अवधि एक से तीन महीने की होती है। एक मैग्नेटिक थेरेपिस्ट प्राइवेट व पब्लिक हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल या वैकल्पिक उपचार चिकित्सा केन्द्रों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक थेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वह उपचार के लिए मैग्नेटिक ज्वैलरी, ब्रेसलेट व अन्य उत्पादों को भी बेच सकते हैं। एक मैग्नेटिक थेरेपिस्ट की आय असीमित है। उनकी आय उनके चिकित्सीय कौशल पर निर्भर करती है। सेल्फ इंपलायड मैग्नेटिक थेरेपिस्ट घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। उनका एक सेशन करीबन 20 से 30 मिनट का होता है।

प्रमुख संस्थान

- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
- एक्यूप्रेशर रिसर्च, टेनिंग व टीटमेंट इंस्टीट्यूट, जोधपुर
- ऑल इंडिया पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल, लुधियाना
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे
- कॉलेज ऑफ क्लिनकिल मैग्नेटोलॉजी और प्राण हीलिंग कॉलेज, त्रिशूर
- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, बैंगलोर
- महेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, जयपुर

एक्वापॉनिक्स फार्मिंग में है बेहतर भविष्य

क्वापोनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक्वाकल्चर जिसमें मछली पालन होता है और दूसरा हाइड्रोपोनिक जिसमें पानी पर खेती होती है। एक्वापोनिक्स में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियाँ और पौधे एक साथ उगाए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत खेती की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है।

आज के समय में एग्रीटेक स्टार्टअप बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। एक्वापोनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक्वाकल्चर जिसमें मछली पालन होता है और दूसरा हाइड्रोपोनिक जिसमें पानी पर खेती होती है। एक्वापोनिक्स में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियाँ और पौधे एक साथ उगाए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत खेती की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है जबकि इसमें पौधे दोगुनी रफ्तार से बढ़ते हैं। एक्वापॉनिक्स में एक फिश टैंक में मछली पालन किया जाता है और दूसरी तरफ पानी पर हाइड्रोपोनिक खेती का सिस्टम बनाया जाता है। फिश टैंक में मछलियां फीड खाने के बाद करीब 70 फीसदी तक मल निकालती हैं जिसमें अमोनिया होता है। इसके बाद फिश टैंक से अमोनिया वाले पानी को हाइड्रोपोनिक खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है तो वहां मौजूद बैक्टीरिया इसे नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। यह पौधों के विकास के लिए बहुत ही अहम होता है। इसके बाद पानी को फिर से प्यूरिफाई किया जाता है और दोबारा मछलियों के टैंक में डाला जाता है। इस तरह एक ही पानी बार-बार इस्तेमाल होता रहता है और पानी की बचत होती है।

एक्वापोनिक फार्मिंग सेटअप तैयार करने में कितनी लागत आएगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बड़ा सेटअप तैयार करना चाहते हैं या छोटा। उदाहरण के लिए अगर आप एक एकड़ जमीन पर एक्वापोनिक फार्मिंग करते हैं तो आपका करीब 3 करोड़ रूपए तक का खर्चा आ सकता है। इसके साथ ही अगर आप मुनाफा चाहते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी वाली चीजें इस्तेमाल करनी होंगी। एक्वापोनिक खेती से हुई पैदावार पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है इसलिए आप इसके लिए सामान्य की तुलना में दो से तीन गुना कीमत कमा सकते हैं। हालाँकि, आपको पैदावार से पहले ही उसे बेचने की तैयारी कर लेनी होगी वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप बड़े-बड़े रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट और फाइव स्टार होटलों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं।

फ्लाइट में यात्रियों की मेहमान नवाजी कर कमाएं हजारों

केबिन क्रू की जिम्मेदारी फ्लाइट में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और यात्रियों को फ्लाइट के नियम समझाना होता है। बहुत से लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि केबिन क्रू कैसे बनें।

केबिन क्रू का मतलब होता है केबिन के कर्मचारी। किसी भी फ्लाइट में जहाँ यात्री बैठते हैं, उसे केबिन कहते हैं। फ्लाइट में यात्रियों की सेवा और सुरक्षा के लिए जो टीम होती है, उसे केबिन क्रू कहते हैं। केबिन क्रू की जिम्मेदारी फ्लाइट में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और यात्रियों को फ्लाइट के नियम समझाना होता है। बहुत से लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि केबिन क्रू कैसे बनें। आज के इस लेख में हम आपको केबिन क्रू बनने के लिए जरूरी योग्यता, प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देंगे

योग्यता

- उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में पास होना चाहिए। या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की हो तो आप केबिन क्रू की जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक की ऊंचाई 157 से 170 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 17 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

जरूरी कौशल

- केबिन क्रू बनने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए।
- केबिन क्रू बनने के लिए दूसरों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने का ढंग होना चाहिए।
- आपके शरीर पर किसी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए।
- आपकी अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
- केबिन क्रू बनने के लिए अच्छी पर्सनालिटी और गुड लुक्स भी जरुरी होते हैं।

कोर्सेज

- डिप्लोमा इन केबिन क्रू एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एयरलाइन एंड ट्रेवल मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एयरलाइन केबिन क्रू
- सर्टिफिकेट कोर्स इन एयर हॉस्टेस

केबिन क्रू कैसे बनें

- एयरलाइन कंपनियां समय-समय पर केबिन क्रू की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती हैं।
- केबिन क्रू का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
- इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आवेदक की शारीरिक जाँच और मेडिकल टेस्ट होता है।
- मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है।
- इन सभी टेस्ट्स को पास करने वाले उम्मीदवारों का चयन केबिन क्रू के लिए होता है।

सैलरी

शुरुआत में बतौर केबिन क्रू आपकी सैलरी प्रतिमाह 30,000 रूपये से 50,000 रूपये तक हो सकती है। हालंकि, समय के साथ अनुभव होने पर सैलरी बढ़कर 70 हजार रूपये से 1 लाख रूपये प्रतिमाह तक हो सकती है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

विवादित लैंड पुलिंग स्कीम मामले में किसानों और विपक्ष की जीत....मान सरकार की हार

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब की मान सरकार द्वारा लाई गई विवादित लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर महीनों से चल रहा विवाद आखिरकार किसानों और विपक्ष की जीत के साथ समाप्त हुआ है। इस योजना का पंजाब के किसानों और विपक्षी पार्टियों ने पुरजोर विरोध किया था, इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल ने भी संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण बताया था। वकील एन.के. वर्मा, संयोजक, बीजेपी लीगल सेल पंजाब ने कहा कि किसानों के अधिकारों और ज़मीन की सुरक्षा के लिए हर मंच पर लड़ाई लड़ी गई। यह योजना किसानों की भूमि पर जबरन नियंत्रण का रास्ता खोल रही थी, जो संवैधानिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से गलत था विपक्ष, किसानों और विभिन्न संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने योजना पर स्टे लगा दिया था। कानूनी दबाव और जनविरोध के चलते अंतत : पंजाब की मान सरकार को पीछे हटते हुए योजना को वापस लेना पड़ा। एडवोकेट वर्मा ने मान सरकार के पीछे हटने को पंजाबियों की ऐतिहासिक जीत ओर आप पार्टी की करारी हार बताकर कहा कि बीजेपी लीगल सेल किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत रहेगी और भविष्य में भी किसी भी जनविरोधी नीति के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोलने से पीछे नहीं हटेगी।

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण वाली याचिका पर 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर को अंतिम सुनवाई होगी। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट के सामने पक्ष रखा। ओबीसी महासभा के वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि कोर्ट ने मामले को अति महत्वपूर्ण मानते हुए टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड किया है। 22 सितंबर को मामले को पहले नंबर पर सुनवाई के लिए रखा है। ये 13 प्रतिशत होल्ड वाले मामले में अंतिम सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं में 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अनहोल्ड किए जाने और छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर अमल के लिए याचिकाकर्ताओं के वकील अपनी बात रख चुके हैं।

हाई कोर्ट ने आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत तक सीमित की थी

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 4 मई 2022 के अंतरिम आदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत तक सीमित कर दी थी। इसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 5 अगस्त को हुई सुनवाई में ओबीसी महासभा की ओर से कहा गया था कि परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन नियुक्ति नहीं दी जा रही है। छत्तीसगढ़ जैसी राहत एमपी में दी जाए। दूसरी तरफ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चांदुरकर की खंडपीठ के सामने अनारक्षित वर्ग द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिए जाने पर बात रखी गई थी।

बिलावल भुट्टो को मिथुन दा की चेतावनी... अगर हमारी खोपड़ी सनक गई

कोलकाता (एजेंसी)। अभिनेता से राजनेता बने भाजपा नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर पलटवार कर कहा है कि अगर

हमारी खोपड़ी सनक गई, फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। कोलकाता में मिथुन दा ने कहा, अगर ऐसी बातें की गई तब हमारी झोपड़ी सनक गई, फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। उनका इशारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बलों की साहसिक कार्रवाई की तरफ था। भाजपा नेता की टिप्पणी बिलावल भुट्टो की उस गीदड़भभकी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया, तब युद्ध होगा। चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री द्वारा सिंधु जल संधि में बदलाव को लेकर भारत को दी गई नई चेतावनी की कड़ी आलोचना की।

20 साल की सज़ा पूरी हुई... रिहा होगा नीतीश कटारा हत्याकांड का दोषी सुखदेव पहलवान

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान उर्फ़ सुखदेव यादव को रिहा करने का आदेश दे दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सुखदेव अपनी 20 साल की सज़ा पूरी कर चुका है। यह फैसला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने स्पष्ट किया कि सुखदेव पहलवान को निश्चित अवधि के लिए उम्रकैद की सज़ा मिली थी, और 20 साल पूरे होने के बाद उसकी रिहाई के लिए अलग से किसी आदेश की ज़रूरत नहीं होना चाहिए है। अदालत ने कहा कि इसतरह के मामलों में, जहाँ सजा की अवधि तय होती है, दोषी को सज़ा पूरी होने पर तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इसके लिए किसी अलग से आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने जेल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाकर यह बात कही। बेंच ने 29 जुलाई को ही सुखदेव पहलवान उर्फ़ सुखदेव यादव को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन सजा समीक्षा बोर्ड ने उसके आचरण का हवाला देकर रिहाई को टाल दिया था। शीर्ष अदालत ने सजा समीक्षा बोर्ड के रवैये पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की की। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बताया कि उसने 29 जुलाई को ही सुखदेव को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन बोर्ड ने उसके आचरण का हवाला देकर रिहाई को टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से पूछा, आखिर आपका यह कैसा बर्ताव है? वहीं मामले में दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने दलील दी थी कि उम्रकैद का मतलब बची हुई पूरी ज़िंदगी जेल में बिताना होता है, और सुखदेव की रिहाई स्वचालित नहीं हो सकती।

देश में एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, आयोग की यह एक नियमित प्रक्रिया है: प्रधान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, वही आज उसकी मूल संस्थानों को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्थान पर निराधार आरोप लगाकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष संशोधित मतदाता सूची (एसआईआर) जैसी नियमित प्रक्रिया को राजनीतिक हथियार बनाकर, यह लोग घुसपैठियों के पक्ष में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि उनके मन में पीड़ा है कि उनके खानदान के बाहर सत्ता कैसे चली गई।

प्रधान ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आए दिन संविधान की दुहाई देते हैं, इन दिनों देश देख रहा है कि सबसे अधिक संविधान-विरोधी कार्य अगर कोई कर रहा है, तो राहुल गांधी उसके सरगना हैं। कांग्रेस पार्टी की

दिशाहीनता, उनकी दुविधा बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग की यह एक नियमित प्रक्रिया है। आजादी के बाद मतदाता सूची को परिष्कृत करने और व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की एक स्वतंत्रत और निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलती है, कभी महाराष्ट्र की बात उठाती है, कभी हरियाणा की बात उठाती है और झूठ का एक नया पहाड़ खड़ा करती है। विशेषकर 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक निराशा की स्थिति में पहुंच चुकी है। उनका कोई स्पष्ट मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यक्रम बना रहे हैं। पहले कांग्रेस ने ईवीएम को मुद्दा बनाया, फिर राफेल पर झूठ बोला, फिर सीमा पर चीन के साथ हमारे विवाद में चीन का साथ दिया। भारत की सेना और भारत की सम्प्रभुता पर इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद ही आजाद भारत में किसी राजनीतिक व्यक्तित्व पर इतनी कटु टिप्पणी दी होगी कि आखिर बताइए, आप हैं किसके साथ?

केन्द्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी आज वैचारिक दिशाहीनता और गहरी दुविधा का पर्याय बन चुके हैं। अराजकता और अहंकार का मेल देश में अस्थिरता फैलाने की उनकी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। उनका स्पष्ट सिद्धांत है कि अगर चुनाव जीतें तो सब कुछ सही, लेकिन हारने पर व्यवस्था में खामियां दिखती हैं। पिछले दो-तीन दिनों में जो बहस और विवाद हुए, विशेष रूप से उस पर भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने तथ्य और प्रमाण के आधार पर लगभग सभी टीवी चैनलों पर राहुल गांधी के एक-एक झूठ का पर्दाफाश किया है। टेक्नोलॉजी, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और देश के सामान्य ज्ञान, इन सभी विषयों पर राहुल गांधी की अज्ञानता उजागर हुई है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी केवल वोट बैंक की राजनीति में लिप्त हैं। घुसपैठियों को वोटर बनाकर, वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। जब चुनाव आयोग, एक संवैधानिक और निष्पक्ष संस्था के रूप में, उन्हें सही तथ्य बताता है, तब वे उसी चुनाव आयोग को ध्वस्त करने की बात करते हैं।

महाराष्ट्र में फिर नाराज दिख रहे एकनाथ शिंदे... बैठक में नहीं हुए शामिल

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है? यह सवाल मंगलवार को फिर से गूंजने लगा है, क्योंकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार इसतरह के संकेत दे रहे हैं। पिछले दिनों वे विधानसभा सत्र के बीच में दिल्ली आए थे। यहां अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। यही नहीं अब मंगलवार को वह प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुंचे। वे रविवार से श्रीनगर में थे, लेकिन उन्हें कैबिनेट मीटिंग के लिए पहुंचना था। लेकिन मीटिंग में वह मौजूद नहीं रहे। कयासों को जोर इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि उनके करीबी मंत्री भारत गोगावाले भी बैठक में नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि शिंदे खुद को और अपने मंत्रियों को नजरअंदाज करने से नाराज चल रहे हैं। भले ही उनके पास फिलहाल विकल्पों की कमी है, इसके बाद साथ छोड़ना मुनासिब नहीं है, लेकिन अंदरखाने नाराजगी बनी हुई है। उनकी एक चिंता यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिवसेना से ज्यादा अजित पवार और उनके लोगों को भाव मिल रहा है।

गोगावाले को लेकर खबर है कि वह रायगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं। अब तक इस जिले में प्रभारी मंत्री का ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि एनसीपी की अदिति तटकरे के नाम पर शिवसेना भड़क गई थी। इसके बाद तटकरे का नाम वापस ले लिया गया, लेकिन अब तक गोगावाले या अन्य किसी का नाम तय भी नहीं हुआ। फिर भी बीच नाराजगी की एक वजह खड़ी हो गई है। वह यह कि अदिति को ही रायगढ़ जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर जाने का मौका मिलेगा। वहीं ध्वज फहराएंगी। इससे शिवसेना में नाराजगी बताई जा रही है। शिवसेना का इस जिले में दावा रहा है कि हमारी स्थिति यहां मजबूत है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेनका गांधी की आपत्ति, कहा- 3 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाना असंभव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के आदेश पर भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अव्यावहारिक, वित्तीय रूप से असंभव और पर्यावरण संतुलन के लिए हानिकारक बताया है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने और अभियान में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद मेनका गांधी ने कहा, कि दिल्ली में करीब 3 लाख कुत्ते हैं। इन्हें हटाने के लिए 3,000 पाउंड (शेल्टर) बनाने होंगे, जिसकी लागत करीब 15,000 करोड़ रुपये होगी। सिर्फ खिलाने में ही हर हफ्ते 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे और डेढ़ लाख देख-रेख करने वाले लोग चाहिए होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आदेश एक फर्जी मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया था कि कुत्ते के हमले से एक लड़की की मौत हुई, जबकि वास्तव में उसकी मौत मेनिनजाइटिस से हुई थी। मेनका गांधी ने कहा कि यह आदेश एक महीने पहले दिए गए सुप्रीम कोर्ट के संतुलित फैसले के विपरीत है।

पर्यावरणीय असर पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कुत्तों को हटाने से बंदरों, चूहों और अन्य जीवों की समस्या बढ़ सकती है, जैसा पेरिस में 1880 के दशक में हुआ था। उन्होंने कुत्तों को रोडेंट कंट्रोल एनिमल बताते हुए मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना को लागू करने की सिफारिश की, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण और रिलोकेशन पर रोक शामिल है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने संकेत दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है और इसे योजनाबद्ध तरीके से हल किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार कहा- जजों को टारगेट करना ट्रेंड बन चुका है, माफी नहीं देंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जजों को टारगेट करना अब ट्रेंड बनता जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज के खिलाफ अपमानजनक आरोपों से जुड़े एक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि वकीलों के बीच न्यायाधीशों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है और इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसलिए माफी का सवाल ही नहीं है। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों से किसी भी तरह से कमतर नहीं हैं।

अवमानना की सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने वकील की माफी स्वीकार करने या याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और सख्त चेतावनी दी, आप अपने मुवक्किल के खिलाफ अवमानना को न्योता दे रहे हैं। ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर करने से पहले, क्या न्यायालय के एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में सावधानी बरतना आपका कर्तव्य नहीं है? अदालत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि स्थापित क़ानून के तहत, ऐसी

याचिकाओं का मसौदा तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने वाले वकील भी अवमानना के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। हालांकि, सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब प्रतिवादी को उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष बिना शर्त माफ़ी मांगने की अनुमति दे दी है, जिसने मूल कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित किया था। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा दी गई 'बिना शर्त और बिना शर्त माफी' पर विचार करते कहा कि इसे एक सप्ताह के भीतर संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष दायर किया जाना चाहिए, जो इसके बाद एक सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेंगे।

बता दें कि यह मामला एक याचिका की सुनवाई के दौरान उठा, जिसमें याचिकाकर्ता, उनके एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और ड्राफ्ट तैयार करने वाले वकील ने कथित तौर पर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए थे। पिछली सुनवाई में अदालत ने इस याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा को गंभीरता से लेते हुए अवमानना नोटिस जारी किए थे। शीर्ष अदालत 29 जुलाई, 2025 को एन पेड्डी राजू के खिलाफ स्वतः संज्ञान दायर एक अवमानना याचिका पर विचार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामले को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कथित तौर पर पक्षपात और अनुचितता का आरोप लगाया था।मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा, हमने देखा है कि आजकल वकीलों के बीच हाई कोर्ट और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की बिना किसी कारण के आलोचना करना एक चलन बन गया है। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही छूट और सम्मान प्राप्त है। पीठ ने आगे कहा कि यद्यपि शीर्ष न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, फिर भी उन्हें ऐसे हमलों से बचाना उसका कर्तव्य है।

पवित्रता का हवाला देकर प्रस्ताव खारिज: ऑनलाइन नहीं बिकेगा पुरी जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद

पुरी (एजेंसी)। ओडिशा सरकार ने साफ कर दिया कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ऑनलाइन बेचने की अनुमति नहीं दे सकती। इस आशय का प्रस्ताव खारित करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि ये महाप्रसाद की पवित्रता का सवाल है इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, महाप्रसाद का गहरा धार्मिक महत्व है और इसे सर्वोच्च सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए। यह पारंपरिक रूप से केवल मंदिर परिसर में ही बेचा जाता है, और अगर इसे ऑनलाइन बेचा गया तो इसकी पवित्रता से समझौता हो सकता है। उनका यह बयान एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा महाप्रसाद बेचने के प्रयास के बाद सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं के जवाब में आया है।

उन्होंने कहा, 'हमें डर है कि अगर 'महाप्रसाद' को इस तरीके से श्रद्धालुओं तक

पहुंचाया गया तो इसकी शुद्धता कायम रह पाएगी या नहीं।' हरिचंदन ने कहा कि सरकार ऐसी किसी भी पहल का समर्थन या प्रचार नहीं करती है। उन्होंने कहा, 'न तो हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव है और न ही हम किसी को 'महाप्रसाद' को ऑनलाइन बेचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।' कानून मंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे 'महाप्रसाद' ग्रहण करने के लिए पुरी जगन्नाथ मंदिर आएं। उन्होंने कहा कि 'महाप्रसाद' के लिए संशोधित दर जल्द लागू की जाएगी। मंत्री का यह बयान मीडिया की उन खबरों के बाद आया है जिनमें भगवान जगन्नाथ के 'महाप्रसाद' की बिना अनुमति ऑनलाइन बिक्री का आरोप लगाया गया है। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के 'महाप्रसाद' की ऑनलाइन बिक्री के कुछ संगठनों के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। हरिचंदन ने यहां सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि कुछ संगठनों ने हाल में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) से पुरी मंदिर के 'महाप्रसाद' और 'सूखा प्रसाद' को ऑनलाइन मंचों के माध्यम से श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, 'दुनियाभर के श्रद्धालुओं को प्रसाद उपलब्ध कराना एक अच्छा विचार था, लेकिन सरकार और एसजेटीए ने प्रसाद की शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।'

इजराइल की हिंसा सच्चाई के लिए खड़े होने का साहस नहीं तोड़ सकती: प्रियंका गांधी

-फिलस्तीन के साथ दिखाई एकजुटता

नई दिल्ली (एजेंसी)। वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गाजा में पांच पत्रकारों की मौत पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर मंगलवार को एक पोस्ट करते हुए कहा, कि यह 'निर्मम हत्या' फिलस्तीनी सरजमीं पर किया गया एक और जघन्य अपराध है, लेकिन इजराइल की हिंसा और नफरत सच्चाई के लिए खड़े होने के असीम साहस को कभी नहीं तोड़ सकती।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गाजा सिटी में पत्रकारों के शिविर पर इजराइली सेना के एक लक्षित हमले में पत्रकार अनस अल-शरीफ और उनके चार सहकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, कि

ऐसी दुनिया में जहां मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और व्यापार का गुलाम बन चुका है, इन बहादुर पत्रकारों ने हमें सच्ची पत्रकारिता का अर्थ याद दिलाया। उनकी आत्मा को शांति मिले।

प्रियंका गांधी गाजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही हैं और फिलस्तीनियों के साथ एकजुटता जता रही हैं। उन्होंने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि निर्दोष नागरिकों और पत्रकारों पर हो रहे हमलों को रोका जाए।

उधर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी रविवार को हुए इस हवाई हमले की कड़ी निंदा की है। संस्था ने पत्रकारों के शिविर को निशाना बनाए जाने को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। गाजा में जारी संघर्ष के बीच पत्रकारों और मीडिया कर्मियों पर बढ़ते हमलों ने प्रेस स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सांसद प्रियंका गांधी के इस बयान को मानवाधिकार संगठनों और प्रेस स्वतंत्रता के पैरोकारों का समर्थन भी मिला है।

अब छिड़ सकती है नई बहस: आरक्षण का हो आर्थिक आधार पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में एससी और एसटी को आरक्षण की सुविधा आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। इस आशय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। याचिका में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अधिक न्यायसंगत व्यवस्था के लिए नीतियां बनाने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद की जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है और 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मसले पर सुनवाई करने के लिए सहमति देने के बाद देश में आरक्षण पर नई बहस छिड़ सकती है।

पीठ ने भी याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह भारी विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस जनहित याचिका के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता संदीप सिंह के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 को मजबूत करेगा और मौजूदा आरक्षण सीमा में बिना किसी छेड़छाड़ के समान अवसर सुनिश्चित करेगा। याचिका में कहा गया है कि दशकों से आरक्षण के बावजूद, आर्थिक रूप से सबसे वंचित लोग अकसर पीछे छूट जाते हैं और आरक्षित श्रेणियों के अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले लोग इसका लाभ उठाते हैं लेकिन आय के आधार पर प्राथमिकता देने से यह सुनिश्चित होगा कि मदद वहीं से शुरू हो जहां आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। जनहित याचिका में कहा गया है, अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों से संबंधित याचिकाकर्ता, वर्तमान याचिका के माध्यम से इन समुदायों के भीतर आर्थिक असमानताओं को उजागर करना चाहते हैं, जिसके कारण मौजूदा आरक्षण नीतियों के तहत लाभों का असमान वितरण हुआ है।

याचिका में यह तर्क भी दिया गया है कि आरक्षण की रूपरेखा शुरू में ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के उत्थान के लिए शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान प्रणाली इन समूहों में अपेक्षाकृत समृद्ध आर्थिक स्तर और उच्च सामाजिक स्थिति वाली पृष्ठभूमि से संबंधित लोगों को असमान रूप से लाभान्वित करती है, जबकि आर्थिक रूप से सबसे वंचित सदस्यों के लिए अवसरों तक सीमित पहुंच होती है। जस्टिस कांत ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कई लोग आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरियों की उच्च श्रेणियों में प्रवेश करके सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं और अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा और सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए कि क्या ऐसे वर्ग के लोगों को अपने ही समुदाय के उन सदस्यों की कीमत पर आरक्षण का लाभ

उठाना जारी रखना चाहिए जो गरीबी में जी रहे हैं और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पूर्व राष्ट्रपतियों से भी खफा ट्रंप?

वाइट हाउस के प्रवेश द्वार से हटवाए ओबामा और बुश के चित्र

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अजग-गजब फैसलों के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। दुनियाभर के कई देशों पर मनमाफिक टैरिफ लगाने के बाद उनके निशाने पर उनके ही देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ट्रंप प्रशासन ने उनके आधिकारिक आवास वाइट हाउस के प्रवेश द्वार पर लगे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के चित्र हटवा दिए हैं और उसे ऐसी जगह पर लगवा दिया है जो कम इस्तेमाल में आता है या जहां बहुत कम लोगों का आना-जाना होता है।

सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वाइट हाउस के प्रवेश द्वार की एक प्रमुख विशेषता रहे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के आधिकारिक चित्र को अब एक कम प्रमुख स्थान पर रखा गया है, जो 44वें और 47वें राष्ट्रपतियों के बीच वर्षों से चले आ रहे तनाव को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ विवादास्पद संबंध रखने वाले अन्य हालिया पूर्ववर्तियों, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और उनके पिता जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश के चित्रों को भी हटा दिया गया है।

वाइट हाउस के रख रखाव में ट्रंप का सीधा दखल : कई स्रोतों ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप वाइट हाउस के रख -रखाव और सौंदर्यीकरण से जुड़े लगभग हर काम में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। वाइट हाउस की परंपरा और प्रोटोकॉल के अनुसार, हाल के राष्ट्रपतियों के चित्रों को कार्यकारी भवन के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता रहा है, जहाँ से आधिकारिक अतिथि और सार्वजनिक पर्यटक आते-जाते हैं। ओबामा का चित्र अब निजी आवास के पास सीढ़ियों के ऊपर, लैंडिंग पर लगाया गया है, जो आम जनता की पहुँच से दूर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबामा की तस्वीर को पुनः स्थापित करने से

रोजाना आने-जाने वाले नहीं देख सकेंगे

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने अपने कर्मचारियों को बराक ओबामा की तस्वीर को ग्रैंड स्टेयरकेस के सबसे ऊपर ले जाने का निर्देश दिया, जो ज़्यादातर उनके परिवार, चुनिंदा कर्मचारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों के लिए ही सीमित था। एक सूत्र ने पुष्टि की कि बुश की तस्वीरें भी अब वहीं रख दी गई हैं। ट्रंप के इस कदम से अब रोजाना वहां आने-जाने वालों की नजरों से बराक ओबामा या बुश जैसे पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें दूर हो गई हैं।

पहले अप्रैल में एक और कदम उठाया गया था, जब इसे ग्रैंड फ़ोयर में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसकी जगह एक पेंटिंग लगाई गई थी, जिसमें पेंसिलवेनिया के बटलर में ट्रंप पर हुए हमले में उनके जीवित बचे होने का चित्रण किया गया है।

रूस को चाहिए एक चौथाई यूक्रेन, ट्रंप-पुतिन की मीटिंग से पहले ही बखेड़ा, जेलेंस्की ने दी चेतावनी

वाशिंगटन/कीव, एजेंसी। अगले हफ्ते होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अहम बैठक से पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे रूस को युद्ध में कब्जा किए गए यूक्रेनी इलाके सौंपने को कतई मंजूर नहीं करेंगे। दरअसल, यूक्रेनी अधिकारियों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार, तीन साल से ज्यादा के इस महायुद्ध में रूसी सेना यूक्रेन के 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुकी है और ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि कब्जा किए यूक्रेनी हिस्सों को रूस को देने में कोई आपत्ति नहीं। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों घोषणा की कि वे 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, जहां वे रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता करेंगे। ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्धविराम समझौता नजदीक है, जिसमें यूक्रेन को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सौंपने पड़ सकते हैं।

जेलेंस्की को यूरोपीय नेताओं का भी समर्थन : यूरोप के कई नेता भी जेलेंस्की के समर्थन में खड़े हुए हैं और यूक्रेन के पक्ष में अपनी एकजुटता जताई है, खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता की उम्मीदें जगी हैं। विश्लेषकों के मुताबिक, यह बैठक वैश्विक राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन जेलेंस्की का यह कड़ा रुख संकेत देता है कि शांति वार्ता में जटिल चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। यूक्रेन की जमीन को लेकर कोई समझौता आसान नहीं होगा।

हर किसी को खुश नहीं कर सकते- वेंस

इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी समझौते से दोनों पक्षों को पूरी तरह खुश नहीं किया जा सकता है। उनका मानना है कि ऐसा कोई भी शांति समझौता जो दोनों देशों द्वारा स्वीकार किया जाए, दोनों के लिए असंतोषजनक होगा। फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में वेंस ने कहा, यह किसी को सुपर खुश नहीं करेगा। शायद अंत में रूस और यूक्रेन दोनों ही इससे खुश नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिका ऐसी शांति की कोशिश कर रहा है जिसे दोनों देश स्वीकार कर सकें।

संक्षिप्त समाचार

भारत चमकती मर्सिडीज और हम लदा ट्रक, आसिम मुनीर ने खुद की पाकिस्तान की बेइज्जती

इस्लामाबाद, एजेंसी। भारत के खिलाफ अकसर जहर उगलने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर फिलहाल ट्रोल किए जा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान की जनता भारत के साथ अपने देश की तुलना करने और कमतर बताने पर ट्रोल कर रही है। आसिम मुनीर ने एक भाषण में कहा था कि भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान बजरी से लदा ट्रक है। आसिम मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह बात कही। उनकी ओर से दोनों देशों की ऐसी तुलना करने पर पाकिस्तानी ही उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कई लोगों ने लिखा है कि आसिम मुनीर तो अपने ही देश की बेइज्जती कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा, मैं साधारण शब्दों में स्थिति का वर्णन करने जा रहा हूं। भारत हाईवेज पर दौड़ती एक चमकती हुई मर्सिडीज या फरारी है। लेकिन हम एक ट्रक हैं, जो बजरी से लदा हुआ है। यदि ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो फिर किसे ज्यादा नुकसान होगा? दरअसल वह पाकिस्तान को चमक से दूर लेकिन एक ताकतवर मुल्क बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुलना ऐसी कर दी कि ट्रोल होने लगे। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, विकास, आबादी की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मानकों पर स्थिति बेहद कमजोर है। ऐसे में पाकिस्तान अकसर हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे जैसी धमकी देता रहता है। भारत के अलावा पाकिस्तान के ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर यह कहते हुए निशाना साधा कि आसिम मुनीर ने खुद स्वीकार कर लिया है कि भारत बेहतर है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, आसिम मुनीर के बयान का यही सच है कि भारत एक मर्सिडीज है, जबकि उनका देश बजरी से लदे ट्रक जैसा है। इसके बाद की सारी बातें एक भ्रम हैं। बता दें कि आसिम मुनीर यह भी धमकी दे चुके हैं कि हम डूबे तो आधी दुनिया को ले जाएंगे। उनके इस बयान से साफ था कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान के अस्तित्व के संकट वाले खौफ से भी गुजर रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान कम से कम अपनी सच्चाई तो जानता है।

17 दिन में 4 देशों ने किया ऐलान

फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बोला- हम भी विचार कर रहे

कैनबरा, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सोमवार को कहा कि इस पर सितंबर में फैसला लिया जाएगा। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा भी फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर चुके है। दो सप्ताह पहले फ्रांस ने जब फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देने का ऐलान किया था, तब अल्बनीज ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रहा है। अब अल्बनीज ने कहा कि अलग फिलिस्तीन देश के तौर पर मान्यता देने का फैसला पिछले दो हफ्तों में ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड और जापान के नेताओं से बातचीत के बाद लिया गया। वहीं, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि उनका देश भी फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के लिए विचार कर रहा है।

अल्बनीज बोले- इजराइल कानून की अनदेखी कर रहा : अल्बनीज ने गाजा की मौजूद हालत को 'दुनिया का सबसे बुरे सपना बताया'। उन्होंने कहा कि इजराइल लगातार अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी कर रहा है। अब पश्चिम एशिया में हिंसा खत्म करने और गाजा में युद्ध, भूख और पीड़ा को रोकने का सबसे अच्छा तरीका टू स्टेट सॉल्यूशन है, जिसमें राजनीतिक रास्ता अपनाया जाए, सैन्य नहीं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर नेतन्याहू से भी बात की। उन्होंने महसूस किया है कि उनके तर्क एक साल पहले के जैसे ही हैं। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि अब सैन्य समाधान नहीं, बल्कि राजनीतिक समाधान की जरूरत है।

अलग देश की मान्यता पर रखी शर्तें

ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के पीछे कुछ शर्तें भी रखी हैं। पीएम अल्बनीज ने कहा कि फिलिस्तीन प्राधिकरण को यह वादा करना होगा कि वह अपने नियंत्रण वाले इलाकों में हथियारबंद गुटों और मिलिशिया को खत्म करेगा। अल्बनीज ने कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भविष्य में होने वाले किसी भी फिलिस्तीनी राज्य में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। अल्बनीज ने कहा कि हमने उस सिस्टम को भी खत्म करने की बात कही है जिसमें इजराइल के लिए लड़ने वाले परिवारों को पैसे दिए जाते हैं। इसे अक्सर 'हत्या की कीमत' कहा जाता है। इसके अलावा अल्बनीज ने आम चुनाव करने और इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को भी मान्यता देने की मांग की।

फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले पर कहा कि एक अलग देश का दर्जा मिलना उनके आत्म निर्णय के अधिकार को बढ़ावा देता है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण वेस्ट बैंक में बनी एक तरह की अस्थायी सरकार है, जिसे 1994 में ओस्लो समझौते के तहत बनाया गया था। इसका काम वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीनी लोगों के लिए प्रशासन चलाना और पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ स्थानीय मामलों की जिम्मेदारी संभालना है।

गाजा में 61 हजार लोगों की मौत: हमास से जुड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में अब तक भूख और कुपोषण से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि अक्टूबर 2023 से चल रही जंग में अब तक 61 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। इजराइली सिक्योरिटी कैबिनेट ने शुक्रवार सुबह गाजा सिटी पर कब्जा करने की मंजूरी दी थी। नेतन्याहू ने कहा कि यह कदम हमास को खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे बंदियों की जान और खतरे में पड़ सकती है और गाजा में संकट और बड़ा हो जाएगा।

फिलिस्तीन के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हुआ

ऑस्ट्रेलियाई पीएम का यह फैसला देश में हजारों फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ताओं और कैबिनेट के कुछ सदस्यों के हफ्तों से जारी दबाव के बाद आया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार को करीब 10 हजार लोगों ने गाजा के समर्थन में एक बड़ा मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने सत्ताधारी लेबर पार्टी और पीएम अल्बनीज के खिलाफ नारे लगाए थे। यह मार्च सिडनी के मशहूर हार्बर ब्रिज पर हुआ, जिसमें लोग गाजा के मानवीय संकट के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे लगाए और गाजा में भुखमरी खत्म करने की मांग की। इस मार्च को फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप ने आयोजित किया था, जिसका मकसद दुनिया का ध्यान गाजा क मुश्किल हालातों की ओर खींचना था।

दक्षिण कोरिया की आर्मी में 20प्रतिशत सैनिकों की कमी, नहीं मिल रहे जवान लड़के

सियोल, एजेंसी। दक्षिण कोरिया की मिलिट्री में सैनिकों की संख्या पिछले छह सालों में 20प्रतिशत कम हो गई है, क्योंकि वहां पुरुषों की तादाद में भारी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण दुनिया में सबसे कम जन्मदर का होना है, जो कि औसतन 0.75 पर है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 20 साल के पुरुषों की संख्या 2019 से 2025 तक 30प्रतिशत घटकर 2 लाख 30 हजार हो गई है। 20 साल की उम्र में ज्यादातर पुरुष मिलिट्री सर्विस के लिए भर्ती होते हैं। अब सेना में अधिकारियों की भी कमी हो रही है और आगे चलकर ऑपरेशन्स में दिक्कतें आ सकती हैं। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद चू मी-ए को यह रिपोर्ट दी गई, जिनके कार्यालय ने इसे जारी किया है। दक्षिण कोरिया की सेना का आकार 2000 के दशक की शुरुआत से लगातार कम हो रहा है, जब इसमें लगभग 6 लाख 90 हजार सैनिक हुआ करते थे। 2010 के दशक के अंत में यह कमी तेज हुई और सेना में करीब 4 लाख 50 हजार सैनिक बचे हैं। वहीं, उत्तर कोरिया के पास 2022 में लगभग 12 लाख सक्रिय सैनिकों की सेना थी।

जापान के क्यूशू द्वीप पर भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन, कई लोग लापता

टोक्यो, एजेंसी। जापान के दक्षिणी क्षेत्र स्थित क्यूशू द्वीप पर भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन ने बड़ी तबाही मचाई है। आपदा के कारण कई लोग घायल हो गए। जबकि द्वीप पर छुट्टी मनाने पहुंचे कई लोग लापता हो गए। क्षेत्र में बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। जापान में पिछले सप्ताह के अंत में शुरू हुई मूसलाधार बारिश के कारण दक्षिणी कागोशिमा प्रांत में एक व्यक्ति लापता हो गया और चार अन्य घायल हो गए। इसके बाद क्यूशू के उत्तरी हिस्सों में और ज्यादा बारिश होने लगी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सोमवार तड़के कुमामोटो में चेतावनी जारी की।

गाजा में आईडीएफ के हमले में मारे गए अल जज़ीरा के 5 पत्रकार, इजरायल का दावा- एक था हमास आतंकी

गाजा, एजेंसी। गाजा पर पूर्ण कब्जे के इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान के बीच इजरायली सुरक्षा बल वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इन हमलों में अल जज़ीरा के कम से कम पाँच पत्रकार मारे गए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा शहर के अल-शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर प्रेस के लिए एक तंबू को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में मारे गए सात लोगों में पांच पत्रकार भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों में अल जज़ीरा के संवाददाता अनस अल-शरीफ और मोहम्मद क़रीक़ेह, साथ ही कैमरामैन इब्राहिम ज़हीर, मोआमेन अलीवा और मोहम्मद नौफ़ल शामिल हैं। इस हमले के तुरंत बाद, इजरायली सेना ने एक बयान में अल जज़ीरा के संवाददाता अनस अल-शरीफ को निशाना बनाने की बात स्वीकार की है और उसे आतंकवादी करार देते हुए कहा कि वह हमास में एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के रूप में काम कर चुका था।

मौत से पहले बमबारी की रिपोर्टिंग : 28 वर्षीय अल-शरीफ अपनी मौत से कुछ क्षण पहले ही गाजा शहर पर हो रहे तीव्र इजरायली बमबारी की रिपोर्टिंग करते हुए

दिखाई दिए। सोशल मीडिया एक्स पर शरीफ ने इस हमले की रिपोर्टिंग करते हुए एक पोस्ट जारी किया था। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह पोस्ट उनके एक मित्र द्वारा पोस्ट की गई है, जो उनके अकाउंट से उनकी मौत की सूचना मिलने के बाद प्रकाशित की गई है। अल-शरीफ के पोस्ट में लिखा गया है, अगर मेरे ये शब्द आप तक पहुंचें तो जान लें कि इजरायल मुझे मारने और मेरी आवाज को दबाने में सफल हो गया है। अल-शरीफ के आखिरी वीडियो के बैकग्राउंड में इजरायल के भीषण बमबारी की तेज आवाज सुनी जा सकती है, जबकि अंधेरा आकाश नारंगी रोशनी की चमक से जगमगा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अल-शरीफ को गाजा युद्ध की धारदार रिपोर्टिंग करने के कारण निशाना बनाया गया है और इजरायल के पास उसके आतंकी होने के कोई सबूत नहीं है। अल जज़ीरा ने अल शरीफ़ को गाज़ा के सबसे बहादुर पत्रकारों में से एक बताते हुए कहा कि यह हमला गाज़ा पर कब्ज़े की आशंका में उठ रही आवाज़ों को दबाने की एक हताश कोशिश है। पत्रकार समूहों और अल जज़ीरा ने हत्याओं की निंदा की। दूसरी तरफ, इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि अल शरीफ़ हमास सेल का प्रमुख था और इजरायली नागरिकों और आईडीएफ (इज़रायली) सैनिकों पर रॉकेट हमलों को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार था।

रूस से तेल खरीदने के चलते चीन पर भी टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप: उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगा दिया है। अब ट्रंप, चीन पर भी रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। ये कहना है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का। एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप, चीन पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं है।

चीन की अमेरिका को दो टूक

सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में चीन का रूसी तेल आयात बढ़कर 10 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, जो मार्च के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मासिक तेल आयात है। हालांकि, इस साल चीन का रूस से कुल

आयात 2024 की तुलना में 7.7 प्रतिशत कम रहा। वहीं अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच चीन ने रूस के साथ अपने ऊर्जा व्यापार का बचाव किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में दो टूक कहा, रूस सहित दुनिया भर के सभी देशों के साथ सामान्य आर्थिक, व्यापारिक और ऊर्जा सहयोग करना चीन के लिए कानूनी तौर पर वैध है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तेल खरीद करते रहेंगे।

अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया

पिछले हफ्ते ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया। इस तरह भारत पर अमेरिका का कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। भारत ने भी अमेरिका के टैरिफ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का ऊर्जा आयात बाज़ार के कारकों और हमारी ऊर्जा जरूरतों से प्रेरित है और इसका उद्देश्य अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

वेंस बोले- चीन पर टैरिफ लगाना अभी तय नहीं

इंटरव्यू के दौरान एंकर ने वेंस से पूछा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाए हैं तो क्या अमेरिका, चीन के खिलाफ भी ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है? इस पर वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। चीन का मुद्दा थोड़ा जटिल है क्योंकि चीन से हमारे रिश्ते ही कुछ ऐसे हैं। रूस की स्थिति को छोड़ दें तो भी चीन पर टैरिफ लगाने से कई अन्य चीजें भी बिगड़ सकती हैं। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है।

तुर्की में 6.1 तीव्रता के साथ हिली धरती, भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स भी, कई इमारतें ढहीं

इस्तांबुल, एजेंसी। तुर्की के उत्तर-पश्चिमी प्रांत बालिकेसिर में रविवार रात को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे करीब एक दर्जन इमारतें ढह गईं। भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप की वजह से मलबे में कम से कम दो लोग फंसे हुए हैं। भूकंप का केंद्र कस्बा सिंदिरगी था और इसके झटके लगभग 200 किलोमीटर दूर इस्तांबुल तक महसूस किए गए, जहां की आबादी 1.6 करोड़ से अधिक है। सिंदिरगी के महापौर सेरकन साक ने बताया कि भूकंप के कारण कस्बे में कई इमारतें गिर गई हैं। बचाव दल ने चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जबकि दो अन्य को मलबे से निकालने का प्रयास जारी है। पास के गोलकुक गांव में भी कई घर ध्वस्त हो गए और एक मस्जिद की मीनार गिर गई।

कई आफ्टरशॉक्स भी

तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स भी महसूस

किए गए, जिनमें एक की तीव्रता 4.6 थी। एजेंसी ने लोगों से क्षतिग्रस्त भवनों से दूर रहने की चेतावनी दी है।

दो साल पहले भूकंप ने ले ली थी हजारों की जान : तुर्की भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है और यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। वर्ष 2023 में तुर्की में आए 7.8 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप में 53,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिससे देश को भारी नुकसान हुआ था।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

लोगों को अपराध से दूर रखने के लिए पुलिस डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी

सूरत में बढ़ते क्राइम रेट पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस का नया प्रयास

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत शहर अपने विकास और प्रगति के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह एक गंभीर सामाजिक समस्या का सामना कर रहा है। छोटी-छोटी बातों में मारपीट, हत्या और हत्या के प्रयास जैसी घटनाएं शहर में बढ़ रही हैं, खासकर उधना, पांडेसरा, गोडादरा, सचिन और भेस्तान जैसे इलाकों में। इस समस्या की जड़ में लोगों में देखा जाने वाला गुस्सा और आक्रोश है, जो क्षणिक आवेग में बड़े अपराधों को जन्म देता है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सूरत पुलिस ने एक अनोखी और नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अपराध रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल का हिस्सा है एक खास डॉक्यूमेंट्री। यह डॉक्यूमेंट्री सूरत पुलिस उन इलाकों में दिखा रही है, जहां सामान्य बातों पर झगड़े और उसके बाद आपराधिक घटनाएं होती हैं और जहां ऐसे आरोपी रहते हैं।

इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसे मामलों को दिखाया गया है, जहां लोग क्षणिक गुस्से में आकर मारपीट और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, और उसके बाद उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि कैसे एक छोटी-सी बात जैसे पान-बीड़ी के झगड़े से शुरू हुआ विवाद, मारपीट और फिर चाकू चलाने तक पहुंच जाता है, और अंत में वह व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। इस घटना का सीधा असर सिर्फ अपराधी पर ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से तबाह हो जाता है।

इस अनोखी मुहिम की शुरुआत उधना पुलिस स्टेशन क्षेत्र से की गई है, जो मारपीट और हत्या जैसे अपराधों के लिए कुख्यात है। इन इलाकों में पुलिस द्वारा प्रोजेक्टर का उपयोग करके खुले में यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, ताकि स्थानीय लोग और उनके परिवार तक यह संदेश सीधे पहुंच सके। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि गुस्सा और आवेग कैसे उनके और उनके परिवार के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री में खुद सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत लोगों से अपील करते नजर आते हैं। वे हिंदी भाषा में लोगों को संयम बनाए रखने और अपने गुस्से पर काबू पाने की सलाह देते हैं। वे उदाहरण देकर समझाते हैं कि कैसे छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और वे बड़े अपराध में बदल जाते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है कि शांति और संयम ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है।

इस डॉक्यूमेंट्री का एक और अहम संदेश यह भी है कि अपराध करने के बाद कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे 20 से 25 साल पुराने मारपीट के मामलों में वांछित आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो रही है। इससे यह साफ होता है कि पुलिस की नजर से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता और कानून का हाथ उसके तक जरूर पहुंचेगा।

यह पहल सिर्फ उधना तक सीमित नहीं है। सूरत पुलिस आने वाले दिनों में शहर के अन्य पुलिस थानों में भी इसी तरह प्रोजेक्टर के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री दिखाकर जागरूकता फैलाएगी। यह प्रयास दर्शाता है कि सूरत पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सूरत पुलिस एक नई दिशा में काम कर रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपराध से दूर रखना और एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना है। यह ऐसा कदम है जो कानून के अमल के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाता है।

चोरी हुई मोपेड के चालान आते हैं, लेकिन पुलिस को मिलती ही नहीं!

सूरत शहर मोपेड मालिक को चार साल में दो चालान और एक कोर्ट का समन मिला

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

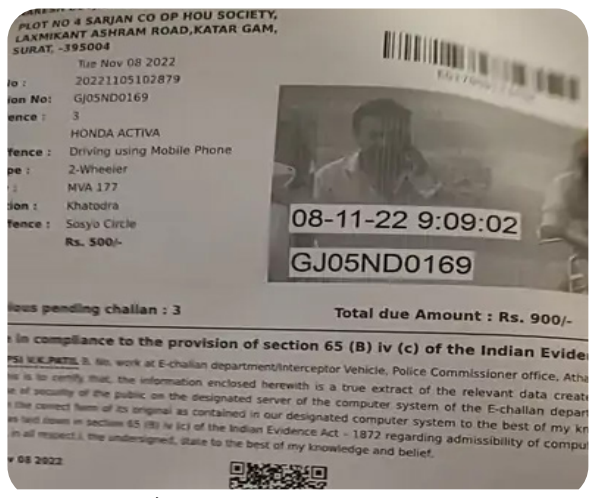

सूरत में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 2021 में अपनी दुकान के बाहर से एक व्यापारी की मोपेड चोरी हो गई थी। इस मामले में कतारगाम पुलिस में आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डेढ़ साल बाद कोर्ट का समन आने पर पता चला कि ट्रैफिक का चालान आया था। मोपेड नहीं मिल रही थी, लेकिन चालान आने शुरू हो गए थे। समन क्लियर करवाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 2025 में तीन महीने पहले बिना हेलमेट के चालान आया। दोबारा पुलिस स्टेशन गए, लेकिन तीन महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर से कोर्ट का समय आने की तैयारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, अमरौली इलाके में रहने वाले नरेशभाई धोला नाम के धागा और जरी के व्यापारी की कतारगाम जीआईडीसी के पास दुकान है। नवंबर 2021 में उनकी दुकान के बाहर से मोपेड चोरी हो गई थी। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। इस बारे में कतारगाम पुलिस में आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मोपेड चोरी होने के कारण वे चिंतित थे, लेकिन मोपेड मिल नहीं रही थी और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इस बीच, 2022 में सोसियो सर्कल के पास फोन पर बात करते हुए मोपेड चलाने का ट्रैफिक चालान जारी हुआ। यह चालान न भरने पर अप्रैल 2023 में कोर्ट का समन आया। फोन पर बात करते हुए ड्राइव करने का चालान भरने के लिए कोर्ट में पेश होने का समन था। मोपेड चोरी होने के बावजूद यह चालान आने पर नरेशभाई हैरान रह गए। इस मामले में कोर्ट सहित कई जगह चक्कर काटने पड़े और आखिर में कतारगाम पुलिस के पास जाने को कहा गया।

2023 में कतारगाम पुलिस स्टेशन गए। उस समय भी चोरी हुई मोपेड की शिकायत दर्ज कर समन रद्द कराने के बाद पुलिस ने हाथ झाड़ लिए। 2023 से 2025 तक नरेशभाई को उम्मीद थी कि उनकी चोरी हुई मोपेड मिल जाएगी। लेकिन 19 अप्रैल को बिना हेलमेट के उनकी ही मोपेड का चालान घर पहुंचा। यह चालान देखकर नरेशभाई फिर से हैरान रह गए। चार साल से मोपेड नहीं मिली, लेकिन कोर्ट का समन और दो चालान घर पहुंच गए।

नरेशभाई धोला ने बताया कि मैंने अपने हाथ से लिखी हुई अर्जी कतारगाम पुलिस को दी थी और बताया था कि मेरी मोपेड चोरी हो गई है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोर्ट का समन व दो चालान मुझे मिले हैं। मेरी मोपेड शहर में ही घूम रही है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। लापरवाही तो है ही, मुझे तो यह भी कहा गया था कि आपकी गाड़ी का नंबर हम सिस्टम में डाल देंगे और 24 घंटे में मिल जाएगी। चार साल हो गए, अभी तक मेरी शिकायत दर्ज नहीं की, सिर्फ मेरे हाथ की लिखी अर्जी ले ली। अब तो मुझे बस मेरी गाड़ी चाहिए, जैसे भी हो मुझे मेरी गाड़ी दिलवाओ।

सख्त पुलिस बंदोबस्त के बीच 18 निर्माण सील

लिंबायत में अलॉटमेंट लेटर बिना अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ पालिका की कार्रवाई,तीखी बहस हुई

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

साल 1994 के आसपास शहर के अठवा गेट, सिविल अस्पताल और बेजान टावर समेत विभिन्न इलाकों में रहने वाले झुग्गीवासियों को नगर निगम द्वारा 1157 लोगों को अलॉटमेंट लेटर के साथ भाठेना स्थित रज़ा नगर में प्लॉट आवंटित किए गए थे। इस इलाके में कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कर रहने की शिकायतें सामने आई थीं। इसी के तहत आज सख्त पुलिस बंदोबस्त के बीच पालिका की टीम ने 18 पक्के और कच्चे निर्माणों को सील किया।

सूरत नगर निगम की ज़मीन पर अवैध झुग्गियां खड़ी किए जाने की शिकायत स्थानीय पार्षदों ने की थी, जिसके बाद लिंबायत ज़ोन ने कुछ समय पहले इस इलाके में सर्वे और दस्तावेज़ों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की थी। झुग्गीवासियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेज़ और सबूतों की जांच के बाद कार्रवाई की गई। झुग्गियों के खिलाफ आज सीलिंग की कार्रवाई के दौरान भारी विरोध हुआ। सख्त पुलिस बंदोबस्त के बीच लिंबायत ज़ोन द्वारा की गई इस कार्रवाई में स्थानीय लोगों के विरोध से माहौल एक समय पर तनावपूर्ण बन गया। दोपहर तक प्रशासन ने 18 संपत्तियों को सील कर दिया था।

लिंबायत ज़ोन के कार्यपालक अभियंता विपुल गणेशवाला ने बताया कि भाठेना क्षेत्र के रज़ा नगर में किए गए सर्वे और दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान करीब 45 झुग्गियां अवैध पाई गईं। इसी के चलते पुलिस बंदोबस्त के साथ अवैध झुग्गियों को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई है। कुल 45 अवैध झुग्गियों में से जो भी निर्माण हैं, उन्हें सील कर दिया जाएगा।

नाश्ते की मामूली बात पर हुई हत्या का राज़ सुलझा, दो युवक गिरफ्तार

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के लिम्बायत इलाके के आस्तिक नगर में हुई एक युवक की हत्या का राज पुलिस ने सुलझा लिया है। अरुण पाटिल नामक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने देवी दास उर्फ़ देवी सुखदेव पाटिल और शनि हलवाई नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, साधारण नाश्ता करने की बात को लेकर मृतक अरुण और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा बढ़ने पर गुस्से में आए आरोपियों ने हथियार से हमला कर अरुण की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की जांच की जा रही है।

पुलिस ने आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस की जांच में आरोपियों ने कबूल किया कि पूरी हत्या झगड़े के बाद ही की गई थी।

5 मिनट तक सार्वजनिक रूप से मारपीट, CCTV में कैद

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के महिधरपुरा इलाके में बंगाली कारीगरों को मकान किराए पर देने को लेकर हुआ विवाद हिंसक रूप ले लिया। एक मकान मालिक और उसके परिवारजनों पर महिला समेत पांच लोगों ने हमला किया। पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज पुलिस को सौंपा गया है। महिधरपुरा पुलिस ने इस मामले में महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ दंगा (रायटिंग) का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

नाराज़ होकर मायके गई पत्नी को वापस लाने में पति का 'पराक्रम' साले के बेटे का ही कर दिया अपहरण

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के सचिन इलाके में तीन साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। शिकायत मिलते ही सचिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बच्चे का अपहरण उसके रिश्तेदार ने ही किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित उसके माता-पिता को सौंप दिया।

यह घटना 10 अगस्त को हुई थी। यहां सुडा सेक्टर-3 में रहने वाले रहीम रजाक मंसूरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका तीन साल का बेटा सोना लापता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक केसरी रंग का गमछा पहने व्यक्ति बच्चे को ले जाता दिखा। आगे की जांच में अपहरणकर्ता की पहचान शिकायतकर्ता रहीम मंसूरी यानी बच्चे के पिता के सगे साले रियाज मंसूरी के रूप में हुई। पुलिस ने तुरंत आरोपी को बिलीमोरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक कंस्ट्रक्शन साइट से पकड़ लिया और बच्चे को सुरक्षित छुड़ाया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी रियाज मंसूरी ने बताया कि उसकी पत्नी पिछले छह महीनों से झगड़ा करके मायके गई हुई है और वापस नहीं आ रही। पत्नी को वापस लाने के लिए उसने साले रहीम मंसूरी से मदद मांगी थी और बीच-बचाव करने की विनती की थी, लेकिन रहीम मंसूरी मदद नहीं कर रहा था। उस पर दबाव बनाने के लिए उसने बच्चे का अपहरण किया।

अनिरुद्धसिंह के पंप पर फायरिंग करवाने वाले हार्दिकसिंह को रस्सी से बांधा

मदुरै के बार से कोच्चि भागा, लेकिन IPS निर्लिप्त राय की SMC टीम से टकराया, चार राज्यों में खोजकर कैसे पकड़ा गया?

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

मदुरै के एक बार में हार्दिकसिंह जाडेजा नाम का शख्स बैठा था। हालांकि, उस समय उसके मन में पकड़े जाने का डर था, इसलिए वह तुरंत वहां से भागकर केरल के कोच्चि पहुंच गया। लेकिन यहां उसका सामना IPS निर्लिप्त राय द्वारा भेजी गई स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) की टीम से हो गया। यही वह हार्दिकसिंह है जिसने 24 जुलाई 2025 की रात करीब 1 बजे गोंडल के रिबड़ा में स्थित अनिरुद्धसिंह जाडेजा के "रिबड़ा पेट्रोलियम" पर फायरिंग करवाई थी। फायरिंग के बाद हार्दिकसिंह ने इंस्टाग्राम पर चार वीडियो स्टोरी डालकर खुद फायरिंग करने का दावा किया था और राजदीपसिंह जाडेजा को खुली धमकी दी थी।हार्दिकसिंह को स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने 18 दिन बाद यानी 11 अगस्त को केरल के कोच्चि से गिरफ्तार किया। हार्दिकसिंह के खिलाफ सूरत के रांदेर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में वह फरार था, इसलिए उसे रांदेर पुलिस को सौंपने की कार्रवाई की गई। इसके बाद राजकोट जिले के गोंडल तालुका पुलिस स्टेशन में दर्ज

"आव्या 3.0"दो दिवसीय वेडिंग एक्ज़ीबिशन आज से

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत,अग्रवाल विकास ट्रस्ट महिला शाखा द्वारा दो दिवसीय वेडिंग एक्ज़ीबिशन "आव्या 3.0" का आयोजन बुधवार से सिटी-लाईट स्थित महाराजा अग्रसेन पैलेस में सुबह दस बजे किया जाएगा। महिला शाखा की अध्यक्षा रुचिका रुंगटा ने बताया कि आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए एक्ज़ीबिशन में डिज़ाइनर ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, होम डेकॉर, मेहंदी सहित शादी के लिए सभी समान एक ही छत के नीचे मिलेंगे। सभी आने वालों को एंट्री पर एश्योर्ड गिफ्ट दिया जाएगा। दो दिवसीय एक्ज़ीबिशन का उद्घाटन आईएएस शिवानी गोयल (डीडीओ) द्वारा किया जाएगा। इस मौक़े पर ट्रस्ट के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।